fo"k; lwph

यूपीए-II प्रथम वर्ष-काला अध्याय
निराशा भरा वर्ष...................... 5
सरकार पर टिके रहना......... 8
साक्षात्कार : अरुण जेटली...... 9
लेख
कहां गया मानवीय चेहरा
संजय कुंदन.................... 10
मजबूरी के नाम पहला साल
राजकुमार सिंह................ 12
सालभर चले अढ़ाई कोस
राजीव सचान.................. 14
श्रद्धांजलि : भैरोंसिंह शेखावत
रुलाकर चल दिए.................... 15
व्यावहारिक राजनेता
अरुण जेटली.................... 20
एक दीप स्तम्भ
श्याम जाजू...................... 22
उन जैसा न जुड़ पायेगा
चंदन मित्रा........................ 24
अन्य
नक्सलवाद पर रुख................ 26
स्पैक्ट्रम घोटाला......................... 28
पुस्तक विमोचन......................... 30

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kekZ
lathr dqekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keZsUæ dkS'ky
fodkl lSuh
सम्पर्क
MkW- eqdthZ Lefr U;kl
ih-ih&66] lqcz.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu u- +91¼11½&23381428
QSDl ¼ +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq ¼ +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ *"गुणाः सर्वत्र पुज्यन्ते।"*
गुणों की सर्वत्र पूजा होती है }

lEikndh;

अजेय योद्धा को विनम्र श्रद्धांजलि

राजस्थान की राजनीति के पर्याय बन चुके भैरोंसिंह शेखावत नहीं रहे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। राजनीति में रहते हुए किसी राज्य का पर्याय बन जाना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। वे राजस्थान के अजेय योद्धा थे। पराजय का मुंह उन्होंने कभी नहीं देखा। दस बार विधायक निर्वाचित होकर उन्होंने कीर्तिमान कायम किया। उन्हें तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

राजस्थान पुलिस सेवा से भारत के उपराष्ट्रपति तक की यात्रा पर एक नजर डालते है तो ऐसा लगता है कि मनुष्य ठान ले तो वह चन्द्रमा पर जा ही नहीं सकता अपितु निवास कर सकता है। शेखावतजी इसी तरह के योद्धा थे। उन्होंने राजनीतिक युद्ध लड़ते हुए सामाजिक संबंधों को बनाए रखा। राजनीति में सरोकार को बनाए रखा। वे मानवीय संबंधों के अटूट पुजारी थे। संबंधों के प्रति वे सदैव समर्पित रहे। राजनीतिक उदारता उनकी वैसी ही थी जैसे लोग अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं।

शानदार धोती–कुर्ता और उस पर जैकेट, काले फ्रेम का चश्मा, कान पर निकले बाल, भौंहें तनी हुईं, चेहरे पर रौब लेकिन होठों पर मुस्कान, ये थी शेखावतजी की पहचान। उन्होंने राजस्थान के मरुस्थल में जनसंघ का दीया अपने खून से जलाया। इतना ही नहीं मरूस्थल से पानी निकालना निश्चित ही कठिन होता है पर राजस्थान को हरा भरा बनाया, खुशहाल बनाया। यही कारण था कि उन्हें अपार जनसमर्थन मिला। विचारधारा की राजनीति करते हुए उदारधारा को सतत् बनाए रखना और उस प्रवाह से सभी को जोड़ना, यह उनकी विशेष विशेषता थी। वे निडर थे। पर लोग उनसे नहीं डरते थे। वे खुले मिजाज के थे। खुलकर बात करते थे, डांटते थे, हंसते थे। कुछ बातें तो भाव भंगिमा से कर लिया करते थे।

शेखावतजी ने सरोकार की राजनीति की। सती प्रथा का विरोध किया, जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन किया, अंत्योदय योजना को साकार किया। निष्पक्षता, आसंदी के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति समर्पण, राज्यसभा के सभापति के रूप में देश ने देखा था। वे न महंत थे, न संत। फिर भी अनेकों के लिए पूज्य थे। वर्तमान भारतीय राजनीति को आज ऐसे ही उदार व्यक्तित्व की परम आवश्यकता है क्योंकि भारतीय राजनीति में पिछले 60 वर्षों से शनैः–शनैः उदारता का डेरा उजड़ता जा रहा है और संकीर्णता से जकड़ता जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि भैरोंसिंह शेखावत नामक राजस्थान के वीर बांकुड़ा हम सबके बीच से चले गए। पर उनके 6 दशक की यात्रा आंखों के सामने सदैव हम सबको स्मरित व रोमांचित करती रहेगी।

वो नाथों के नाथ थे। किसी के लिए एकनाथ तो किसी के लिए सोमनाथ

थे। आज लोग मनुष्य के बीच नफरत फैलाते हैं, उन्होंने मनुष्य को जोड़ा, संस्कारित किया, सैद्धांतिक पक्ष से जोड़ा। हम सभी राजस्थान के शेखावटी माटी को प्रणाम करते हैं, शत्–शत् नमन करते हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति को ऐसा उदारचित्त व्यक्ति का धनी व्यक्तित्व प्रदत्त किया।

हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज की भारतीय राजनीति में उदात्त मन से उदारता भरी राजनीति की ओर बढ़ना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

यूपीए-२ का प्रथम वर्ष - काला अध्याय

यूपीए–2 का एक वर्ष बीत गया। जो सरकार चला रहे हैं वे कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया। सरकार की सफलता पर उन्हें नाज है परन्तु देश की जनता अनाज को तरस रही है। महंगाई से मर रही है। भूख मौत का कारण बन रही है। बाजार की महंगी गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। सरकार हाथ का पंखा तक छीन रही है। शायद अच्छा यह होता कि यूपीए जनता के मर्म को समझती। जनसमस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाती पर यूपीए का सच यह है कि वह झूठ के कारोबार पर ही टिकी है। वह झूठ को माता–पिता मानती है, त्वमेव झूठम, त्वमेव सर्वम्।

जन–झूठ का एक वर्ष बीत गया। हम सीमाओं पर आतंकवादियों से पिट रहे हैं। घर में नक्सलियों से पिट रहे हैं। हम गुप्तचरी में फेल हो रहे हैं। एक सीमापार पर चीन तो दूसरे पर पाकिस्तान, नित आंखें दिखा रहा है। सीमाओं पर घट रही घटनाएं स्वयं कमजोरी का अहसास कराती हैं। पर यूपीए–2 पता नहीं क्यों एक वर्ष पर जश्न मनाने में मशगूल है। वह जश्न का कारण बताए। जनता जानना चाहती है। एक वर्ष बीता यह सच है पर एक वर्ष में क्या हुआ, क्यों इस सच को वह निगल रही है? अफजल और कसाब आज भी प्रश्नचिह्न बने हुए हैं। बावजूद इसके कि माओवादी, आतंकवादी रोज खून की नदियां बहा रहे हैं। योजनाओं को अपने पुरखे के नाम कर लेना, गांधी उपनाम से नामाकरण कर लेना, मां अध्यक्ष–बेटा महामंत्री जैसी पार्टी चला लेना स्वयं यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस में न दम बचा है और न कोई दमदार बचा है। यूपीए–सेकेंड, हर सेकेंड, राजनैतिक अपराध कर रही है। ममता, मायावती, करूणानिधि, शरद पवार के कांग्रेस के साथ जो व्यवहार हैं, वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सत्ता की चाशनी ही सबको जोड़े हुए है तथा किसी तरीके से सत्ता में बने रहना और सौदेबाजी ही इनका एकमात्र लक्ष्य है।

यूपीए–2 के प्रधानमंत्री में बदलाव थोड़ा जरूर आया है। पहले यूपीए में वो सोनिया की सब बातें नहीं मानते थे। यूपीए–2 में वो सोनिया से पूछे बिना कुछ करते नहीं हैं। यूपीए संवैधानिक और केन्द्र से जुड़े संस्थानों सीबीआई आदि का राजनैतिक दुरुपयोग कर जिस तरीके से अपना संकीर्ण स्वार्थ साध रही है, उससे लगता है कि यूपीए–2 प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखती है। प्रतिशोध की राजनीति का परिणाम देश ने आपातकाल के रूप में देखा है।

यूपीए को समझना चाहिए कि यह अधिक दिनों नहीं चलने वाला है। किसानों का मरना जारी, बेरोजगारी का बढ़ना जारी, रोटी–कपड़ा–मकान के सवाल जस के तस, गरीबी घट नहीं रही, उलटे बढ़ रही है। 21वीं सदी की भारत बनाने का सपना यूपीए ने चूर–चूर कर दिया। यूपीए–2 के एक वर्ष में न ताल है, न सुर है, न रियाज की तैयारी है। अगर हालात यही रहे तो इसमें कोई दो मत नहीं कि यूपीए अपने कर्मों से विदाई की तैयारी कर रही है। ■

कोली/कोरी समाज का भाजपा को समर्थन

अखिल भारतीय युवा कोली/कोरी समाज (रजि.) दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खेमचंद कोली व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में लगभग तीस लोगों का एक प्रतिनिधिमण्डल भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय 11 अशोक रोड पर 9 मई, 2010 को मिला। उक्त प्रतिनिधि मण्डल से विशेष भेंट हेतु गडकरी जी बाहर प्रांगण में आए जहां उन्हें भगवान गौतम बुद्ध का एक सुन्दर चित्र भेंट किया गया व पुष्प मालाएं डालकर सभी ने उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी व खुशी जाहिर की। श्री खेमचंद कोली ने कोली समाज को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न जारी करने पर रोष व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में कोरी समाज को एससी सर्टिफिकेट न दिए जाने पर विस्तृत बातचीत की गई। श्री गडकरी जी ने दोनों राज्यों में एससी सर्टिफिकेट दिलवाने में मदद का आश्वासन दिया तो श्री खेमचंद कोली ने भी भारत के कई सारे राज्यों में भाजपा का समर्थन करने का वादा किया। निकट भविष्य में एक विशाल कार्यक्रम कोली/कोरी समाज द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसमें कि श्री नितिन गडकरी ने मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया अंत में संस्था की ओर से सबका मुंह मीठा करवाया गया। ■

संप्रग-II का पहला वर्ष निराशा भरा वर्ष : भाजपा

संप्रग सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। आम चुनावों के बाद पहला वर्ष आमतौर पर उत्साह से भरपूर वर्ष होता है। विडंबना देखिए, संप्रग–II का पहला वर्ष निराशा भरा वर्ष रहा है। यह ऐसा वर्ष है, जिसमें कोई उपलब्धि नहीं हुई; यह कुशासन, असंगति, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का वर्ष रहा है।

उपलब्धि

संप्रग की एकमात्र उपलब्धि यह तथ्य है, जिसकी वह शेखी बघार सकता है कि यह सत्ता में बना रहा। संप्रग का लोकसभा में कमजोर बहुमत है। राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है। लोकसभा में इसका बहुमत अपने कतिपय तत्कालीन सहयोगी दलों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार करने के कारण क्षीण होता प्रतीत हो रहा है। इसका सत्ता में बने रहने का कारण कोई आपवादिक प्रदर्शन या लोकप्रिय समर्थन नहीं है। यह केवल इसलिए है कि इसने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कतिपय मित्र दलों के साथ समझौता किया है और प्रतिपक्ष के कतिपय कमजोर वर्गों को मैनेज करने में कामयाबी पाई है।

तृणमूल कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय आवंटित किया गया है। किन्तु, तृणमूल की प्राथमिकता शासन चलाना नहीं है। डीएमके के अंदर परिवार के विभाजनों का विस्तार आर्थिक लूट में हिस्सेदारी तक हो चुका है। जब 2–जी स्पैक्ट्रम के आवंटन में बहुत बड़ी धोखा–धड़ी की तरफ इंगित किया गया था,, तब प्रधानमंत्री जी के इसकी अनदेखी करने से यूपीए–डीएमके गठजोड़ को मजबूत करने में सहायता मिली थी। सीबीआई का दुरूपयोग करके प्रतिपक्ष के कमजोर तबकों को, जिसमें बसपा, सपा और राजद शामिल थे, मैनेज कर लिया गया था। 2010 के कटौती प्रस्ताव और 2008 के विश्वासमत प्रस्ताव ने इन पार्टियों को मैनेज करने में सीबीआई की सार्थकता को स्थापित कर दिया था, जिनके नेता उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के केसों के कारण मैनेज किए जाने योग्य है। संप्रग के पास राजनेताओं को मैनेज करने का यही राजनैतिक कौशल है, जिसकी उपलब्धि का संप्रग दावा कर सकता है।

मूल्यवृद्धि

संप्रग–II का प्रमाण–चिन्ह मूल्यों में वृद्धि और अर्थव्यवस्था का कु–प्रबंधन रहा है। संप्रग के पहले वर्ष में पूरे समय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना अयोग के उपाध्यक्ष राष्ट्र को जानकारी देते रहे कि मूल्य–विशेषतया खाद्य पदार्थों के मूल्य शीघ्र कम होंगे। मगर प्रथम वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर दो अंकों में पहुंच गया तथा खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 17–19 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था का कु–प्रबंधन इस तथ्य से प्रकट होता है कि खाद्यान्न गोदामों में पड़े सड़ते रहे, किंतु बाजार में सप्लाई संबंधी समस्या बनी रही, जिसने खाद्यान्नों के मूल्यों को बेलगाम कर दिया।

विदेश नीति

संप्रग के प्रथम वर्ष में भारत को स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसरण को तिलांजलि देते हुए पाया गया। सामरिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय दबावों के विरूद्ध भारत परंपरागत रूप में जिस मजबूती से खड़ा हुआ करता था, वह मजबूती गायब रही। शरमल शेख की संयुक्त घोषणा का आधार जनवरी 2004 कम्युनिकेशन की भावना के विपरीत था। संप्रग सरकार की यह नीति है कि चाहे पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का प्रयोग आतंकवादियों को करने देने से रोकता है या नहीं, इस पर विचार किए बिना समग्र वार्ता जारी रहेगी। विदेश सचिव स्तर की वार्ताओं तथा दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता की नए सिरे से शुरू की गई पहलों का अब यही आधार है। यह भारत की सदैव से पारंपरिक रूप से अपनाई गई स्थिति के प्रतिकूल है। कोपनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की भूमिका अमेरिका के दबाव के सामने भारत के घुटने टेकने का एक अन्य उदाहरण है। सिविल न्यूक्लियर दायित्व विधेयक भी अनिवार्यतः अमेरिकी दबाव के तहत लाया गया है, हालांकि भारत में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर इसका लागू किया जाना प्रथम दृष्टया इस विधेयक को निरर्थक तथा असंगत बनाता है।

माओवादी हिंसा और सीमापार आतंकवाद

भारत सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव डालने में अपनी स्थिति को कमजोर बनाता प्रतीत होता है। पाकिस्तान से 26/11 ट्रॉयल

पर प्राप्त हुआ सहयोग का स्तर निराशाजनक रहा है। यह तथ्य कि तहकीकात करने वाली और खुफिया एजेंसियां अपने आप डेविड हेडली के ब्यौरों की खोज नहीं कर सकीं, हमारी खुफिया एजेंसियों की स्थिति का घटिया चित्र प्रस्तुत करता है। 26/11 के ट्रायल के परिणामस्वरूप केवल एक दोषसिद्धि अर्थात् अजमल कसाब की दोषसिद्धि हो पायी है। अन्य के बारे में या तो हमें सहयोग नहीं मिला या कोई साक्ष्य नहीं मिला। स्पष्टतः, इतना बड़ा हमला केवल एक व्यक्ति द्वारा प्लान नहीं किया जा सकता था।

माओवादी बगावत का भी देश में भारी विस्तार हुआ है। संप्रग–I या तो समस्या की मौजूदगी से या इसके संभावित समाधान से अनजान था। संप्रग–II के अधीन गृहमंत्रालय ने माओवादी हिंसा से निपटने में अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक रवैया अपनाने के शुरूआती संकेत दिये थे। मगर इस रवैये के प्रति प्रतिपक्ष के समर्थन के बावजूद, संप्रग ने माओवाद विरूद्ध लड़ाई कमजोर कर दी और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय भ्रम पैदा कर दिया। संप्रग ने स्पष्टतः माओवादी हिंसा से लड़ने की इच्छा को गंवा दिया है। दीर्घावधि में विकास ही निश्चित रूप में इसकी प्रतिक्रिया होती है, किंतु अराजकता की स्थिति में कोई विकास नहीं किया जा सकता है। जरूरी यह है कि हिंसा और अव्यवस्था पर काबू पाया जाए।

भ्रष्टाचार

संप्रग–I के शासनकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में कमी देखी गई थी। ऐसा संविदा आदि देने के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। संप्रग–II के शासनकाल में जब 2–जी स्पैक्ट्रम के आवंटन में राष्ट्रीय राजकोष को लगभग 60,000 करोड़ रूपए की हानि हुई थी, तब प्रधानमंत्री अपना ध्यान कहीं अन्यत्र लगाए हुए थे। जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाते है, तब प्रधानमंत्री जी ने दूसरी तरफ मुंह करना शुरू कर दिया है।

मंत्रीय असामंजस्य

संप्रग की एक अन्य विशेषता मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं के बीच असामंजस्य रहना रही है। गृहमंत्री पर जब उनकी अपनी पार्टी की ओर से हमले किए गए तब उन्होंने अपनी असहायता दिखाई। उन्होंने रिकार्ड पर कहा कि यद्यपि माओवाद से लडने के लिए दो तरफा रणनीति मौजूद है, पर एक तरफ की अर्थात् सुरक्षा रणनीति हाल के घटनाक्रम से कमजोर पड़ गई है। आईपीएल फ्रैंचाइज़ के वास्ते या चीन की कम्पनियों के वास्ते मंत्रियों का समर्थन अब संप्रग का स्वीकार्य व्यवहार बन गया है।

संस्थाओं का विनाशन

ऐसी विभिन्न संस्थाओं पर हमला किया जाता है, जो लोकतंत्र के प्रभावी कार्यचालन हेतु आवश्यक है। सीबीआई का शर्मनाक दुरूपयोग संप्रग के शासन का एक स्थायी लक्षण बन गया है। जब संप्रग–I के पांचवे वर्ष में वामदल समर्थन वापसी की कगार पर थे तब मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके विरूद्ध सीबीआई द्वारा केस का हल्का किया जाना एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब 2010 में संप्रग–II के शासनकाल में कटौती प्रस्ताव से संप्रग पर संकट मंडराया था तब बसपा की मुखिया सुश्री मायावती का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई केस को हल्का कर दिया गया। राजद नेता लालू प्रसाद यादव आय से अधिक संपत्ति रखने के वास्ते सीबीआई केस को मैनेज किए जाने के रूप में ऋण चुकाने के लिए तत्पर हैं। संप्रग–I के दौरान दलगत नियुक्ति के माध्यम से निर्वाचन आयोग में टांका लगाया गया था। संप्रग–II के दौरान राजनीतिक प्रतिपक्ष को मैनेज करने तथा संभालने में अधिकृत और अनधिकृत टेलिफोन टैपिंग की गई। सरकार के अंदर और बाहर लाबिस्ट सक्रिय हैं। विभागों के आवंटन तक में उनकी लिप्तता के बारे में हाल का साक्ष्य भारतीय राजनीति के लिए नया कानून बन गया है।

प्रतिपक्ष तथा भाजपा

संप्रग–II के प्रथम वर्ष ने वास्तविक प्रतिपक्ष और कृत्रिम प्रतिपक्ष के बीच विभेद को स्पष्ट कर दिया। कमजोर नेताओं के नेतृत्व वाले कुछ राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से प्रतिपक्ष को पलीता लगाया था उससे भारतीय राजनीति में गैर–संप्रग का स्थान लेने के लिए वास्तविक प्रतिपक्ष को मजबूती देने में भारी सहायता मिलेगी।

हम भाजपा वालों के लिए यह एक यादगार वर्ष रहा। हमारी पार्टी को नए अध्यक्ष और संसद के दोनों सदनों को पार्टी का नया नेतृत्व मिला। पार्टी संगठन को राज्य स्तर तक पुनर्संरचित किया गया है। दल की गतिविधियां देशभर में फैली हैं। भारत के सभी भागों में संप्रग की राजनीतिक विफलता के विरूद्ध पार्टी के कैडर को सक्रिय विरोध प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। संसद के दोनों सदनों में हमारी पार्टी ने कई अवसरों पर सरकार को बैक–फुट पर लाया है। हम राष्ट्रीय प्रतिपक्ष के एतिहासिक दायित्व को पूरा करने के लिए कृत–संकल्प हैं।

भाजपा का विश्वास है कि चार वर्ष के पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेस में महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई उत्तर नहीं दिया है। भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जिन मूल प्रश्नों के उत्तर देने को टाल दिया वे हैं :–

1. आपकी सरकार ने खाद्य वस्तुओं ⏭

दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने विजेन्द्र गुप्ता

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लिए श्री विजेन्द्र गुप्ता को मनोनीत किया है। विदित हो कि श्री विजेन्द्र गुप्ता दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के चेयरमैन रहे हैं। रोहिणी क्षेत्र से तीन बार निगम पार्षद का चुनाव जीत चुके श्री गुप्ता ने जनप्रिय प्रतिनिधि के तौर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सन् 2009 के लोकसभा चुनाव में वे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। सन् 1984–85 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष रहे श्री गुप्ता भाजपा पीतमपुरा मंडल के महामंत्री भी रह चुके हैं। ■

सूर्य प्रताप शाही बने उप्र भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) श्री सूर्य प्रताप शाही को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है। मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी श्री शाही कसिया से विधायक रह चुके हैं। वे श्री कल्याण सिंह, श्री रामप्रकाश गुप्ता और श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। श्री शाही उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ■

रामसेवक पैकरा भाजपा छत्तीसगढ़ के निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित

गत 10 मई, 2010 को श्री रामसेवक पैकरा छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुये। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक श्री जुएल ओराम ने उनके निर्वाचन की घोषणा की।

अनंत कुमार बिहार प्रदेश भाजपा प्रभारी नियुक्त, धर्मेन्द्र प्रधान बने सहप्रभारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नितिन गडकरी ने बिहार प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार (राष्ट्रीय महामंत्री) व सह–प्रभारी श्री धर्मेन्द्र प्रधान (राष्ट्रीय महामंत्री) के नामों की नियुक्ति की है। ■

श्रीकांत शर्मा बने मीडिया सेल के राष्ट्रीय संयोजक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पार्टी के मीडिया सेल के सह–संयोजक श्रीकांत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे श्री शर्मा सन् 1991 में पीजीडीएवी महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा 1992–93 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सचिव पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। ■

⏭की मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा क्या कदम उठाए जाएंगे?

2. माओवादी हिंसा से निपटने के लिए रणनीति के बारे में संप्रग के अंदर मतभेदों को शमन करने के लिए आपका क्या इरादा है?
3. पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू करने से पहले क्या आप आश्वस्त है कि पाकिस्तान के नियंत्रण भू–क्षेत्र के किसी भी भाग को भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाएगा?
4. क्या आप स्वीकार करते हैं कि 2–जी स्पैक्ट्रम के आवंटन में अनियमिताओं और अनौचित्यों के कारण राजकोष को भारी हानि हुई है?
5. इस सुझाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि 2008 में विश्वास मत और 2010 में कटौती प्रस्ताव के दौरान कुछ विरोधी दलों के कतिपय कमजोर नेताओं को मैनेज करने में सीबीआई ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ■

संप्रग की उपलब्धि, सरकार में टिके रहना

;|- पी.ए. सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर, भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा, महंगाई के खिलाफ जन्तर–मन्तर पर 24 मई को विशाल धरना आयोजित किया गया तथा इसे काले दिवस की संज्ञा प्रदान की गई। सभी कार्यकर्त्ताओं ने विरोध के रूप में अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधी हुई थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने हजारों कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित किया। इस काले दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, वाणी त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, डॉ. हर्ष वर्धन एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रो. जगदीश मुखी एवं दिल्ली प्रदेश पदाधिकारी अब्दुल रशीद, पवन शर्मा, विशाखा शैलानी, हरबंस डंकल, रमेश बिधूड़ी, सरदार आर.पी. सिंह, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, विरेन्द्र सचदेवा, कमलजीत सहरावत, रामचरण गुजराती के अलावा विधायक ओ.पी. बब्बर, करण सिंह तंवर, कुलवंत राणा, साहब सिंह चौहान, मोहन सिंह बिष्ट, सतप्रकाश राणा, श्रीकृष्ण त्यागी, डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता, दिल्ली नगर निगम पदाधिकारी सुभाष आर्य व योगेन्द्र चांदोलिया एवं सभी निगम पार्षद, जिलों के अध्यक्ष, सभी मोर्चो, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज ने यू.पी.ए. सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को 'काला वर्ष' बताया। श्रीमती स्वराज ने कहा कि यू.पी.ए. सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके घटक दल अलग–अलग दिशाओं में सरकार की खींचतान पूरे वर्ष करते रहे हैं और इसके मंत्रियों के मनमाने बयानों से, सरकार का पूरा वर्ष सफाई देते ही बीत गया। जिसका प्रतिफल महंगाई व जनविरोधी नीतियाँ है।

यूपीए के कुशासन के खिलाफ जन्तर–मन्तर पर आयोजित विशाल प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली एवं अन्य पार्टी नेतागण

दिल्ली संप्रग–2 सरकार के पहले साल को बेहद निराशाजनक करार देते हुए भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने दो टूक कहा कि सरकार की एक मात्र उपलब्धि किसी तरह सत्ता में टिके रहना रहा। इसके लिए सत्ता के सहयोगियों को खुली लूट का मौका दिया गया तो बाहरी समर्थकों को साधने के लिए सीबीआई का जमकर दुरुपयोग हुआ। जेटली ने प्रधानमंत्री की पत्रकार वार्ता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जब उन्हें महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने ही नहीं थे तो इसे बुलाया ही क्यों गयाघ जेटली ने एक–एक कर सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की जमकर खबर ली। उन्होंने कहा कि साल भर सरकार कैसे चली यह सामने है। महंगाई पर बड़े–बड़े दावे किए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। माओवादी हिंसा से निपटने की बजाय वह मोर्चे से भागती रही। पाकिस्तान को झुकाने के बजाय वह खुद ही झुकती रही। भ्रष्टाचार तो एक तरह से सरकारी तंत्र का हिस्सा ही बना रहा। भाजपा नेता ने कहा कि आम तौर पर किसी भी सरकार का पहला साल उत्साह से भरा होता है, लेकिन इस सरकार से तो आम जनता को निराशा ही हाथ लगी। पूरे साल कुशासन, असंगति, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला रहा। सरकार के साथी उसे लूटने में लगे रहे और प्रधानमंत्री आंख मूंदे देखते रहे। तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता सरकार चलाने से इतर रही तो द्रमुक के घर

...शेष पृष्ठ 11 पर

राजनैतिक हेराफेरी पर टिकी है सरकार : जेटली

यूपीए–II के एक वर्ष की पूर्णता पर नवभारत टाइम्स के पत्रकार ने राज्यसभा में भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली से विशेष वार्ता की। हम यहाँ उस वार्ता के कुछ प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

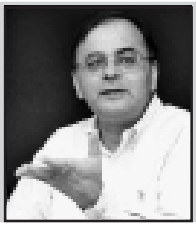

- यूपीए-२ पहले साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है?

यह एक निराशाजनक साल रहा है। पहला साल अक्सर हनीमून पीरियड के लिए होता है। हनीमूल पीरियड के दौरान सरकार पर दबाव कम होता है इसलिए वह लोकप्रिय कदम उठा सकती है। यह भी संभावना हो सकती है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष थोड़ा कमजोर हो, लेकिन सरकार की स्थिति विचित्र रही। इसने आरंभ किया अहंकार की मुद्रा में। वामपंथी इनसे दुखी हो चुके थे क्योंकि साढ़े चार साल तक उनके दम पर यूपीए ने अपनी सरकार चलाई और फिर उनके साथ विश्वासघात किया। एसपी और आरजेडी को संदेश दे दिया गया कि आपकी आवश्यकता नहीं है। एक साल में सरकार राजनैतिक हेराफेरी या मैंनेजमेंट के माध्यम से सत्ता में रही है। कभी सीबीआई का दुरूपयोग तो कभी अन्य हथकंडे अपनाए गए। यदि 2008 के विश्वास मत के मतदान और 2010 के कटौती प्रस्ताव पर मतदान को देखें तो एक ही बात नजर आती है। जिस तरह भ्रष्टाचार के मुकदमों के माध्यम से 2008 में मुलायम सिंह का समर्थन लिया गया उसी तरह इस बार मायावती पर दबाव डाल कर उनका समर्थन हासिल किया गया। इन हथकंडों के माध्यम से सरकार चला लेने को यदि उपलब्धि कहना हो तो यह यूपीए की उपलब्धि है।

- आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर यूपीए का काम किस प्रकार का रहा?

प्रधानमंत्री की रेपुटेशन अर्थशास्त्री की रही है लेकिन वह एक साल से कह रहे हैं कि कीमतें कम होंगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फूड ग्रेन के भंडार सड़ रहे हैं और उन्हें चूहे खा रहे हैं। सरकार सप्लाई लाइन ठीक नहीं कर पा रही है और कीमतें कम नहीं हो रही हैं। माओवादी आतंक के खिलाफ लगता कि अपने पूर्ववर्ती मंत्री की तुलना में चिदंबरम की समझ बेहतर है। वह कड़े कदम उठाएंगे। चिदंबरम की भाषा भी ठीक थी जो हमें स्वीकार्य थी। लेकिन अचानक उन्हें पुलडाउन किया गया और उनकी लाइन का विरोध किया गया। यह सरकार के अन्य नेताओं ने किया। आज पूरी तरह सरकार में कन्फ्यूजन है कि माओवादी आतंक से कैसे निपटा जाए। जहां तक आतंकवाद का सवाल है आज भी इन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क सुधार किया हो ऐसा नहीं लगता।

- विदेश नीति का आपका आकलन क्या है?

न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, शर्म अल शेख, विदेश, सचिव वार्ता, कोपनहेगन क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना आदि पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि सरकार ने 2004 की अपनी पुरानी लाइन बदल डाली। 2004 से जो नीति बनी थी, उसमें तय हुआ था कि तब तक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी जब तक पाकिस्तान अपनी भूमि का प्रयोग आतंक के लिए होने देता रहेगा। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने उस नीति को छोड़ कर उसके स्थान पर शर्म अल शेख की लाइन ले ली कि आतंकवाद अलग विषय है लेकिन बातचीत चलती रहेगी। सरकार की नीति पर गौर करें तो साफ पता लगता है कि अमेरिका का दबाव इसकी विदेश नीति पर है। मुझे कई बार डर लगता है कि इतिहास में अपना नाम लिखवाने की होड़ में सरकार का नेतृत्व कश्मीर मुद्दे पर कोई बुनियादी समझौता न कर ले।

- यूपीए सरकार के कामकाज के बारे में और क्या कहेंगे?

मंत्रिमंडलीय अनुशासन पर नजर डालें तो भ्रष्टाचार आसमान पर पहुंच गया है। थ्री– जी की नीलामी से स्पष्ट हो गया कि यदि टू–जी की नीलामी ऐसे की गई होती तो बहुत बड़ा दाम मिलता। यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें सरकार को 60 हजार करोड़ रूपये का घाटा हुआ। प्रधानमंत्री मजबूर दिख रहे हैं। वह कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जिस मंत्री की मर्जी में जो आता है, बोल देता है। कोई चीन की कंपनियों की वकालत करने लगता है तो कोई आईपीएल की फ्रेंचाइजी की छीना झपटी में उलझ जाता है।

- तो क्या यूपीए की कोई उपलब्धि नहीं है?

महिला आरक्षण बिल बीजेपी की पहल, उसके दबाव और उसके वोट से पारित हुआ। संसद के उस सदन में पारित हुआ जिसमें कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। जहां तक शिक्षा के अधिकार का सवाल है तो वह अभी कागज पर है। वित्तीय आवंटन तो अभी होना है उसे वास्तविक रूप से लागू करने के लिए। किसानों के ऋण माफ किए गए लेकिन क्या उससे उनकी किस्मत बदल चुकी है? नरेगा का कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है। कार्यक्रम से कोई मतभेद नहीं है लेकिन उसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीर मुद्दे खड़े हैं। ■

कहां गया वह मानवीय चेहरा

l।t ; d।nu

Vपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने के बाद यूपीए सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ जरूर थपथपा सकती है कि उसने विपक्ष के हर दांव की हवा निकाल कर, उसके खेमे में तोड़फोड़ कर फिलहाल सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन सच यह है कि वह उस आम आदमी का विश्वास खोती जा रही है, जिसके भीतर ढेरों आशाएं जगाकर वह दोबारा दिल्ली का सिंहासन पाने में कामयाब हुई थी। अपने पहले कार्यकाल में नरेगा और दूसरी कुछ योजनाओं के जरिए यूपीए ने खुद को गांवों और गरीबों के हमदर्द के तौर पर पेश किया था। साधारण जन ने सरकार के रवैये में अपने लिए उम्मीदें देखीं और इसे एक बार फिर सत्ता सौंप दी।

मंत्रियों का बड़बोलापन

ऐसा लग रहा था कि सरकार ने जो कार्य शुरू किए थे, उन्हें अब वह मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उसने जो सदिच्छाएं दिखाईं, वे कार्यरूप में परिणत होंगी पर हुआ उलटा। यूपीए–2 की शुरुआत के साथ ही सरकार और जनता के बीच एक स्पष्ट फांक पैदा हो गई। आज अनेक मंत्री अपने रंग–ढंग में जन प्रतिनिधि से ज्यादा नौकरशाह नजर आ रहे हैं। हालांकि यह स्थिति कमोबेश यूपीए–1 के समय से ही बन गई थी। तब भी एक तरह की 'अराजनीतिक' सरकार नजर आती थी पर आज की तरह उसमें बेरुखी नहीं दिखती थी, न ही उसके नुमाइंदों में इस कदर बड़बोलापन था। लेकिन यूपीए–2 के कुछ मंत्री तो जनता के प्रति संवेदनशील रुख अपनाने के बजाय अपने आचरण और बयानों से उसके जख्मों पर नमक छिड़कने में लगे हुए हैं, जिससे सरकार की पहले वाली प्रो–पीपल इमेज का मुलम्मा उतरने लगा है।

संवेदनशीलता की कमी

सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रियों एसएम कृष्णा और शशि थरूर (अब भूतपूर्व) के महंगे होटलों में ठहरने की बात सामने आई। उन्होंने अपने इस कदम को सही ठहराकर अपनी ही पार्टी के सादगी अभियान को कठघरे में खड़ा कर दिया। थरूर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कैटल क्लास वाली टिप्पणी करके आम आदमी की भावनाओं पर गहरा आघात किया। उसके बाद महंगाई को लेकर कृषि मंत्री शरद पवार ने जो रवैया दिखाया उससे भी जनता को काफी ठेस लगी। वह लोगों को आश्वासन कहां से देते, उलटे और डराते ही रहे। वह चीनी की कीमत बढ़ने की बात करते रहे और कीमत बढ़ती रही। जब उनसे पूछा गया कि यह सिलसिला कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा कि वह कोई ज्योतिषी तो हैं नहीं जो भविष्यवाणी कर सकें। रेल मंत्री ममता बनर्जी ने तो अपने महकमे को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। सरकार के पहले महीने में बीस दिन वह दिल्ली से गायब रहीं। अब भी वह राजधानी में नहीं रहना चाहतीं। मंत्रिमंडल की बैठकों में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। रेलवे से जुड़े कई अहम फैसले उनकी गैर मौजूदगी में लिए गए। पिछले दिनों जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना घटी तो उन्होंने लोगों के आंसू पोंछने के बजाय उलटे उन्हीं के ऊपर दोष मढ़ दिया। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने चीन में गृह मंत्रालय की आलोचना कर अपनी ही सरकार की स्थिति हास्यास्पद बना दी। ऐसा करके वह एक चीनी कंपनी की तरफदारी करते हुए नजर आए। कुछेक अपवाद को छोड़ दें तो ज्यादातर मंत्री न तो खुद को कुशल प्रशासक साबित कर पा रहे हैं, न जिम्मेदार राजनेता। कुछेक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं।

मंत्रियों को क्या कहें, खुद प्रधानमंत्री ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे साधारण आदमी इस सरकार से अपना जुड़ाव महसूस कर सके। महंगाई जैसे अहम मुद्दे पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया।

मंत्रियों को क्या कहें, खुद प्रधानमंत्री ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे साधारण आदमी इस सरकार से अपना जुड़ाव महसूस कर सके। महंगाई जैसे अहम मुद्दे पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। देश जानता है कि पीएम कई मामलों में लाचार हैं, पर उनसे दो मीठे बोल बोलना भी गवारा न हुआ। कई अखबारों और चैनलों के सर्वे में उन्हें सफल प्रधानमंत्री बताया गया है। जो पीएम महत्वपूर्ण फैसले न ले सके, जो अपने ही भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई न कर सके, जो महंगाई की जिम्मेदारी कृषि मंत्री पर टाल दे, जो एक साल में संसद सत्र के दौरान तीन अहम मौकों पर अनुपस्थित रहे, वह भी

अगर लोकप्रिय है, तो समझा जा सकता है कि देश में नेतृत्व का संकट कितना गहरा है। डॉ. सिंह ने अमेरिका से दोस्ती मजबूत करने और पाकिस्तान से संबंध सुधारने पर ज्यादा जोर दिया है जो कि जरूरी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इतनी ही ऊर्जा घरेलू समस्याओं को दूर करने में खर्च की होती तो शायद इसका ज्यादा फायदा होता।

आज महंगाई के मोर्चे पर सरकार धराशायी नजर आ रही है।

प्रश्न है कि क्या सोनिया गांधी यूपीए सरकार को जनता के प्रति संवेदनशील बना पाएंगी? क्या वह अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों को जवाबदेह बना पाएंगी? सियासी मजबूरियों के बीच एक बेहतर सरकार देना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सरकार और जनता के बीच पैदा हो रही खाई को पाटने की तत्काल कोशिश नहीं की गई तो यूपीए सरकार के लिए आगे की राह और मुश्किल हो सकती है।

आतंकवादी घटनाओं पर रोक तो लगी है लेकिन दंतेवाड़ा में दूसरी बार अपनी खूनी कारवाई से माओवादियों ने साबित कर दिया है कि प्रशासन का उन पर कोई जोर नहीं चल रहा। बहरहाल इस स्थिति में भी जनता से संवाद बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव राहुल गांधी ने संभाल रखी है। सोनिया गांधी सरकार के मानवीय चेहरे को बचाए रखना चाहती हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं रह गया है। एक जवाबदेह राजनेता के रूप में वह जिस रूप में सोच रही हैं, उसी रूप में उनकी 'अराजनीतिक' सरकार नहीं सोचती।

मुश्किल है राह

सूचना के अधिकार को लेकर उनमें और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद को इसी रूप में देखा जा सकता है। सोनिया गांधी ने इस कानून को लागू कराने में अहम भूमिका निभाई थी लेकिन मनमोहन सिंह और उनकी टीम इसमें संशोधन कर जनता को मिले अधिकार में कटौती करना चाहती है। इसी तरह फूड सिक्युरिटी बिल को लेकर सोनिया गांधी के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय सवाल उठा रहा है। प्रश्न है कि क्या सोनिया गांधी यूपीए सरकार को जनता के प्रति संवेदनशील बना पाएंगी? क्या वह अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों को जवाबदेह बना पाएंगी? सियासी मजबूरियों के बीच एक बेहतर सरकार देना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सरकार और जनता के बीच पैदा हो रही खाई को पाटने की तत्काल कोशिश नहीं की गई तो यूपीए सरकार के लिए आगे की राह और मुश्किल हो सकती है। *(साभार)* ■

...पृष्ठ 8 का शेष

के झगड़े में सभी आर्थिक लूट में लगे रहे। सीबीआई तो अपना असली काम छोड़कर सरकार को संसद में बहुमत दिलाने के लिए जुटी रही। इसमें किस दल को कैसे मैनेज (साधना) करना है यह उसकी प्राथमिकता में रहा। जेटली ने तीखे कटाक्ष करते हुए सरकार पर एक–एक कर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अब सरकार अपनी पीठ ठोंक रही है तो किस बात पर? इस पर कि प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री व योजना आयोग के दावों के बावजूद महंगाई बेलगाम बढ़ती रही? नक्सली सुरक्षा बलों के साथ आम नागरिकों को मारते रहे और केंद्र सरकार बयानों से बरगलाने में लगी रही? प्रधानमंत्री माओवादी हिंसा को देश की संप्रभुता को खतरा करार देते रहे और गृहमंत्री राज्यों के भरोसे लड़ाई छोड़कर कहते रहे कि हम तो केवल सहायता भर करेंगे? जिस पाकिस्तान को वाजपेयी सरकार ने झुका कर रख दिया था, वह आंखे चढ़ाकर देख रहा है? भाजपा नेता ने कहा अब तो इस सरकार की अकर्मण्यता की हद हो गई है कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी के मामले पर उसकी सरकार खुद फाइल दबाकर बैठी है और कह रही है कि कानून अपना काम करेगा। 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर फैसला होगा, जैसे कोई सिनेमा का टिकट या फुटबाल मैच के टिकट हो।

प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने अपने सम्बोधन में कहा कि यू.पी.ए. सरकार की एक वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रिकार्ड तोड़ महंगाई है। इसके कार्यकाल में स्कूल की फीस, बसों मेट्रो के किराये, पेट्रोल–डीजल, सी.एन.जी. के दाम न केवल बढ़े हैं वरन् खाने–पीने की वस्तुऐं दूध इत्यादि के दाम तो आसमान छू रहे हैं। जिसके प्रति विशेषकर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की संवेदनहीनता जनता को जले पर नमक छिड़कने की याद दिलाती है। लोग निराश, हताश हैं और अपनी इसी भावना को काले दिवस के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, डॉ. हर्ष वर्धन एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रो. जगदीश मुखी ने भी प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया और यू.पी.ए. सरकार की विफलताओं तथा काले दिवस के आयोजन की प्रासंगिकता को उजागर किया। ■

मनमोहन सरकार : मजबूरी के नाम पहला साल

jkt dekj flg

dk ग्रेसी रुझान वाले राजनीतिक पंडित और मनमोहन सिंह के प्रशंसक तर्क दे सकते हैं कि पांच साल के लिए चुनी गयी सरकार के कामकाज का आकलन वार्षिक आधार पर नहीं होना चाहिए, पर जब चुनाव के दौरान समयबद्ध लक्ष्य घोषित कर वायदे किये गये हों तथा सरकार बनते ही मंत्रालयों में 100 दिन के एजेंडे की होड़ लग गयी हो तब तो यह आकलन अनिवार्य ही हो जाता है। यह आकलन इसलिए भी तर्कसंगत लगता है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार पहली बार अथवा अप्रत्याशित रूप से केंद्रीय सत्ता में पदारूढ़ नहीं हुई है कि उसे विरासत में मिली स्थितियों का आकलन कर अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए वक्त चाहिए।

दरअसल मनमोहन सिंह सरकार पांच वर्ष का अपना एक कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर और बेहतर जनादेश के साथ सत्ता में लौटी है। इसलिए उसके पास यह विकल्प था कि बिना किन्हीं औपचारिकताओं में वक्त गंवाये अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करने में जुट जाती। पिछले वर्ष अप्रैल–मई की भीषण गर्मी में हुए पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस ने मतदाताओं को सपना भी यही दिखाया था। उससे पहले वर्ष 2004 में हुए चौदहवीं लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं ने भाजपाई नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नीचे से कुर्सी खींच कर कांग्रेस को अप्रत्याशित रूप से सौंपी थी, तब उसने अपना हाथ आम आदमी के साथ होने का वायदा किया था। विपक्ष के इस प्रचार पर पूरा यकीन न भी किया जाये कि वह हाथ साथ होने के बजाय आम आदमी की जेब से होता हुआ उसकी गर्दन तक ही पहुंच गया तब भी बेलगाम महंगाई और किसानों की आत्महत्या से संदेश तो यही मिला कि वायदा निभाया नहीं गया।

इसके बावजूद अगर मतदाताओं ने कांग्रेस और मनमोहन सिंह को दूसरा मौका दिया तो मानना चाहिए कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत में वैसा असर न दिखने तथा बेहतर विकल्प उपलब्ध न होने का लाभ मिला। कम से कम कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा कांग्रेसियों की भी अपेक्षा से अधिक 200 के पार पहुंच जाने का तो यही अर्थ है। शुरुआती हैरानी के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं में भी यह आत्मविश्वास दिखाए पर मंत्रिमंडल गठन में ही करुणानिधि के द्रमुक और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जैसी कवायद करा दी, उससे सारा उत्साह उडन छू हो गया और किसी हद तक साख भी।

विडंबना है कि कमान भले ही मनमोहन सिंह के हाथ में नज़र आती हो, पर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर ही उनका कोई नियंत्रण नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि केंद्र में संप्रग के बैनर तले गठित इस सरकार का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की सत्ता सोनिया गांधी की मुट्ठी में है। इसलिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए नाम 10 जनपथ से ही आते हैं और मनमोहन सिंह सरकार की भूमिका उन पर मोहर लगाने की औपचारिकता पूरी करने तक ही सीमित रहती है। यह भी जगजाहिर सच्चाई है कि गठबंधन सरकार राजनीतिक मजबूरी की देन होती है, इसलिए कई तरह के वांछित–अवांछित समझौते करने पड़ते हैं, पर कोई गठबंधन इतना मजबूर और गठबंधन सरकार इतनी निरंकुश भी हो सकती है, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल से पहले की होगी।

द्रमुक के ए. राजा सबसे बदनाम भले ही हों, पर मनमोहन सिंह सरकार की शर्मिंदगी का कारण बनने वाले इकलौते मंत्री हरगिज नहीं हैं। द्रमुक सुप्रीमो करुणानिधि के पुत्र अलागिरी तो न संसद में आते हैं और न ही अपने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

खुद कांग्रेस के मंत्रियों का भी हाल अलग नहीं है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा और विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने पांच सितारा होटल में रहने की फिजूलखर्ची से सरकार को शर्मिंदा किया। थरूर तो आईपीएल की कोच्चि टीम में अपनी महिला मित्र को मिली मुफ्त हिस्सेदारी और अपने पद के दुरुपयोग के प्रकरण में बेआबरू होकर कूचे से विदा हो गये, लेकिन शर्म अल शेख आदि के शर्मनाक वाकयों के बावजूद कृष्णा अभी तक बरकरार हैं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश तो चीन में अपनी सरकार के गृह मंत्रालय की आलोचना की अभूतपूर्व कारगुजारी के बावजूद सरकार में बने हुए हैं।

के कामकाम में रुचि लेते नजर आते हैं। बेशक ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू और जनाधार वाली राजनेत्री की रही है। वह अतीत में भी मंत्री रही हैं, पर इस मंत्रित्वकाल में तो वह पूरी तरह निरंकुश नजर आती हैं। याद करें कि सरकार बनने के कुछ महीने तक किस तरह रेल मंत्रालय कोलकाता से ही चलता नजर आया। ममता बनर्जी के हस्ताक्षर लेने के लिए फाइलें कोलकाता भेजी जाती थीं। इस एक वर्ष में ही वह एक दर्जन से भी अधिक केबिनेट बैठकों से गैर–हाजिर रह चुकी हैं। माना कि रेल दुर्घटनाएं रोकने का कोई गारंटीशुदा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसी रविवार को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए यात्रियों को ही जिम्मेदार ठहराने वाला उनका बयान तो गैर–जिम्मेदारी के साथ–साथ संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा है।

माओवादी हिंसा को प्रधानमंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, लेकिन माओवादियों से रिश्तों को लेकर ममता लगातार कठघरे में हैं। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए कि ममता के बिना सरकार नहीं चल सकती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी मनमोहन सिंह सरकार के लिए मुश्किलें ही ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। बेशक पवार भी जनाधार वाले नेता हैं। उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन कृषि, खाद्य–आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के केबिनेट मंत्री के रूप में उनकी नाकामी इस सरकार को बहुत भारी पड़ रही है।

बेलगाम महंगाई मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर सामने आयेगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री चिंता जताने और फिर जिम्मेदारी राज्य सरकारों के सिर मढने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जिस विलय को संसद की स्थायी समिति ने पूरी तरह गलत और सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला बताया, वह केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की ही देन था।

अपने–अपने मंत्रालयों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ संभाल पाने में नाकाम ये दोनों मंत्री क्रिकेट की राजनीति, खासकर आईपीएल के गोरखधंधे में अपनी संलिप्तता के चलते भी सरकार को शर्मिंदा करते रहे हैं, पर प्रधानमंत्री पूरी तरह असहाय नजर आते हैं। कांग्रेस और प्रधानमंत्री के पैरोकार इस नाकामी को गठबंधन राजनीति की मजबूरी की आड़ में छिपाते हुए कह सकते हैं कि अन्यथा सरकार अपने वायदों और प्राथमिकताओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध और प्रयत्नशील है, लेकिन मतदाता को इस मजबूरी से क्या लेना–देना?

आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी मनमोहन सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आती है। नक्सलवाद से निपटने के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह भ्रमित नजर आती है। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद केंद्रीय गृहमंत्री तो बदल गये हैं, पर आतंकवाद या नक्सलवाद के विरुद्ध कोई स्पष्ट और ठोस नीति आज तक नजर नहीं आती।

खुद कांग्रेस के मंत्रियों का भी हाल अलग नहीं है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा और विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने पांच सितारा होटल में रहने की फिजूलखर्ची से सरकार को शर्मिंदा किया। थरूर तो आईपीएल की कोच्चि टीम में अपनी महिला मित्र को मिली मुफ्त हिस्सेदारी और अपने पद के दुरुपयोग के प्रकरण में बेआबरू होकर कूचे से विदा हो गये, लेकिन शर्म अल शेख आदि के शर्मनाक वाकयों के बावजूद कृष्णा अभी तक बरकरार हैं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश तो चीन में अपनी सरकार के गृह मंत्रालय की आलोचना की अभूतपूर्व कारगुजारी के बावजूद सरकार में बने हुए हैं।

आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी मनमोहन सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आती है। नक्सलवाद से निपटने के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह भ्रमित नजर आती है। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद केंद्रीय गृहमंत्री तो बदल गये हैं, पर आतंकवाद या नक्सलवाद के विरुद्ध कोई स्पष्ट और ठोस नीति आज तक नजर नहीं आती।

मनमोहन सिंह सरकार ने शैक्षणिक और विधि सुधार सरीखी कुछ महत्वाकांक्षी पहल की हैं, लेकिन ये अभी घोषणाओं के स्तर पर ही हैं। हां, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार का देश की अर्थव्यवस्था पर वैसा हाहाकारी असर न होने तथा आर्थिक विकास दर के वापस रफ्तार पकडने का श्रेय अवश्य मनमोहन सिंह सरकार को देना चाहिए, पर ये उपलब्धियां नाकामियों के मुकाबले बहुत कमजोर नजर आती हैं। इसलिए भी कि इनका असर आम आदमी तक देर से पहुंचता है, जबकि महंगाई और नक्सलवाद की मार तत्काल महसूस हो जाती है। फिर बेहतर बहुमत के बावजूद राजनीतिक मोर्चे पर भी यह सरकार कई बार, यहां तक कि संसद के अंदर भी, लडखड़ाती नजर आयी है। राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर पाना बड़ी उपलब्धि है या लोकसभा में पेश न कर पाना बड़ी नाकामी.यह फैसला फिलहाल समय पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। ■

साल भर चले अढ़ाई कोस

jktho lpku

eनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि संप्रग शासन की दूसरी पारी का एक साल पूरा होने पर उसकी ओर से उपलब्धियों के ढोल बजाए जाएंगे। यह गुणगान चाहे जितना बढ़–चढ़कर किया जाए, इससे इनकार नहीं कि विपक्ष यानी असली विपक्ष अर्थात् राजग और वामदलों की ओर से केंद्र सरकार की कथित सफलताओं को सिरे से खारिज किया जाएगा। निःसंदेह बसपा, सपा और राजद की भी केंद्र सरकार के एक वर्ष के कामकाज पर कोई न कोई राय होगी, लेकिन उनकी राय का इसलिए कोई मूल्य–महत्व नहीं, क्योंकि ये दल संसद के बाहर कुछ कहते हैं और संसद के भीतर कुछ और।

लाख सफाई क्यों न दी जाए, सच्चाई यह है कि माया–मुलायम–लालू को या तो सीबीआई के जरिये डराया गया या फिर दिलासा दिया गया। आज के दिन इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता कि सीबीआई को स्वायत्तता है और उसके कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं। मनमोहन सरकार ने सीबीआई को पुलिस चौकी बनाकर रख दिया है। सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव–प्रभाव में काम ही नहीं करती, बल्कि बिना विचारे उसका हुक्म बजाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो बोफोर्स दलाल क्वात्रोची के लंदन स्थित बैंकों के खातों पर लगी रोक हटाने का काम उसके हाथों नहीं होता। यह काम संप्रग के पिछले शासन में हुआ था। इस बार सीबीआई के जरिये माया–मुलायम–लालू से समर्थन हासिल किया गया और 2–जी स्पेक्ट्रम में गोलमाल करने के आरोपी दूरसंचार मंत्री ए राजा को राहत दी गई। सीबीआई के उन अधिकारियों को जांच से हटा दिया गया जो इस गोलमाल की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। राजा के जिक्र से यह याद आना स्वाभाविक है कि मनमोहन सिंह का अलागिरी, ममता बनर्जी और शरद पवार पर कोई जोर नहीं।

पवार का नाम लेते ही न केवल महंगाई याद आती है, बल्कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता भी। कोई सरकार महंगाई से न लड़ पाए तो अफसोस किया जा सकता है, लेकिन जो उससे लड़ना ही न चाहे उसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो लोग यह मान रहे हैं कि केवल खाने–पीने की वस्तुएं ही बेतहाशा महंगी हुई हैं वे भ्रम में हैं, क्योंकि आम जरूरत की कोई भी चीज महंगाई से अछूती नहीं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के मूल्यों का तो और भी बुरा हाल है। यदि मनमोहन सरकार केवल घटक दलों के मंत्रियों के सामने असहाय होती तो भी गनीमत होती और शायद उसे गठबंधन सरकार की मजबूरी मानकर सहन कर लिया जाता, लेकिन उसका तो कांग्रेसी नेताओं पर ही कोई जोर नहीं।

कई कांग्रेसी नेता जिस तरह केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम की घेराबंदी करने में जुटे हैं उससे यह साफ है कि केंद्रीय गृहमंत्री नक्सलियों से आर–पार की लड़ाई तब तक नहीं लड़ सकते जब तक दिग्विजय सिंह एंड कंपनी को परास्त नहीं कर लेते। कांग्रेस नेतृत्व यह जान रहा है कि दिग्विजय सिंह गृहमंत्री के खिलाफ निजी खुन्नस निकाल रहे हैं, लेकिन वह उन्हें पूरी छूट दिए हुए है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार दोहरा चुके हैं कि नक्सली आंतरिक

मनमोहन सरकार ने सीबीआई को पुलिस चौकी बनाकर रख दिया है। सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव–प्रभाव में काम ही नहीं करती, बल्कि बिना विचारे उसका हुक्म बजाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो बोफोर्स दलाल क्वात्रोची के लंदन स्थित बैंकों के खातों पर लगी रोक हटाने का काम उसके हाथों नहीं होता। यह काम संप्रग के पिछले शासन में हुआ था। इस बार सीबीआई के जरिये माया–मुलायम–लालू से समर्थन हासिल किया गया और 2.जी स्पेक्ट्रम में गोलमाल करने के आरोपी दूरसंचार मंत्री ए राजा को राहत दी गई।

...शेष पृष्ठ 25 पर

नम आंखों से दी शेखावत को अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने आए देशभर से नेता

रुला कर चल दिए

...बाबा तेरा नाम रहेगा

पचरंगी साफे में सजे राजनीतिक समर के महानायक पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत की अंतिम यात्रा सवेरे ज्योंहि सरकारी निवास से निकली, सैकड़ों लोगों ने लरजते गलों से 'बाबा तेरा नाम रहेगा' के नारों से माहौल को गुंजा दिया। वहीं आवास के बाहर खड़े बैण्ड ने रघुपति राघव राजा राम की धुन बजा कर बाबोसा की अंतिम विदाई की बेला का ऐलान कर दिया। सुबह से बाबोसा की एक झलक पाने और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। सेना के वाहन में बाबोसा के पार्थिक शरीर नम आखों से

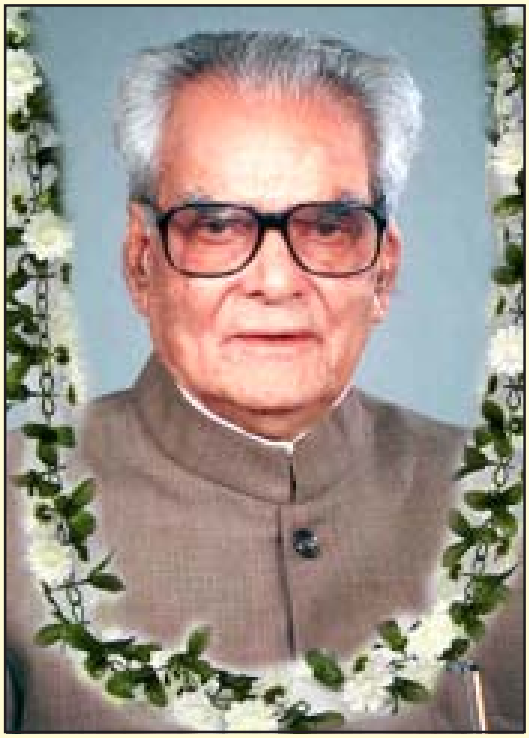

हजारों हाथों ने नमन किया और फिर यात्रा के साथ हो लिए। 16 मई की सुबह करीब पौने ग्यारह बजे सिविल लाइन्स स्थित सरकारी आवास पर शेखावत का पार्थिव शरीर सेना के वाहन में रखा गया। उनके परिजनों के साथ नाती भी वाहन में सवार हुए और अंतिम यात्रा आगे के लिए रवाना हो गई। आगे–आगे मातमी धुनें बजाता बैण्ड, पीछे वाहन में शेखावत का पार्थिव शरीर और उसके बाद अपने चहेते नेता की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ जनसमूह। चिलचिलाती धूप में भी राजधानी के लोग 14 किलोमीटर लम्बी अंतिम यात्रा में बाबोसा के अंतिम दर्शनों के लिए बाजारों, चौराहों, गलियों और घरों में खड़े ⏭

टूट गयी तिकड़ी

अटलजी, आडवाणीजी और शेखावतजी की तिकड़ी 15 मई को टूट गई। तीनों ही जन संघ के संस्थापकों में रहे हैं। 1952 में बनी इस तिकड़ी का एक–एक सदस्य विशिष्ट था। इसमें अब आडवाणीजी ही स्वस्थ और सक्रिय हैं। वाजपेयीजी बीमारी के कारण पिछले तीन–चार सालों से पूरी तरह सक्रिय नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। 1947 में देश विभाजन के बाद श्री लालकृष्ण आडवाणी को राजस्थान में प्रचारक का जिम्मा सौंपा गया। बाद में वह

गुजरात चले गए। जन संघ के गठन के समय शेखावतजी और आडवाणीजी, अटलजी के संपर्क में आए थे। तब से तीनों के बीच मित्रता गहरी होती चली गई और अंत तक रही।

इस तिकड़ी के तीनों ही नेता अपने क्षेत्र में महारथी रहे। अटलजी प्रधानमंत्री बने तो शेखावतजी तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति बने। जबकि आडवाणीजी गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। इनमें खास बात यह थी कि तीनों हफ्ते में एक दिन किसी न किसी के घर खाने पर मिलते थे। ■

अंतिम

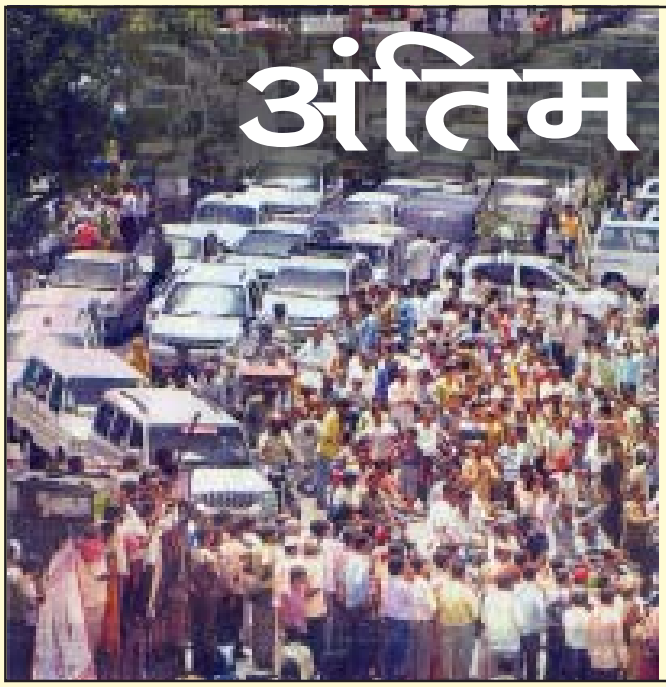

...थे। बाइस गोदाम होते हुए आए काफिले का पहला पड़ाव सरदार पटेल मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय था। यहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समेत सैंकड़ों कार्यकर्ता पांच दशक से अधिक समय से पार्टी को मार्गदर्शन देने वाले अपने सम्माननीय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे। भाजपा मुख्यालय के बाहर शेखावत के अंतिम दर्शनों के लिए ऊंचा मंच बना था। यहां भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष नितिन गड़करी, महासचिव अनंत कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा कार्यालय पर पुष्पांजलि के बाद शेखावत की अंतिम यात्रा का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। पार्टी कार्यालय से निकलने के बाद यात्रा चारीदवारी के मुख्य बाजारों के लिए रवाना हुई। रास्ते में विभिन्न राजनीतिक, व्यापारिक और कर्मचारियों संगठनों के अलावा आमजन ने भी शेखावत के पार्थिक शरीर पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धाजंलि दी। कई लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने के दौरान अंतिम यात्रा में रो पड़े। चारदीवारी में सैंकड़ों लोग शेखावत की अंतिम यात्रा में उन्हें पुष्प अर्पित करने और बाद में यात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही डटे हुए थे। हर जुबान पर यही था कि अब शायद ही ऐसा कोई जमीन से जुड़ा इंसान राजनीति में आए, जो आमजन की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। पांच बत्ती पर विधायक राजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शेखावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए। यहीं से कुछ दूर एमआई रोड व्यापार मण्डल से जुड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों ने पुष्प चक्र चढ़ाया। न्यू गेट के बाद सांगानेरी गेट पर विधायक अशोक परनामी और आमजन ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित अश्रुपूर्ण श्रद्धाजंलि अर्पित की। सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के मंहत परिवार ने भी शेखावत को पुष्प अर्पित किए। जौहरी बाजार में लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा कर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। बड़ी चौपड़ पर व्यापार मण्डल और कई संगठनों ने शेखावत को पुष्पचक्र व पुष्प अर्पित किए। छोटी चौपड़ पर व्यापार मण्डल

अटल बिहारी

शोक

श्री भैरों सिंह शेखावत के निधन
राजनेता, कद्दावर राजनीतिज्ञ और माटी का सपूत हम
श्री शेखावत शुरू से जनसंघ और
रहे। पार्टी की नींव के पत्थरों में से वे एक थे। वे
दलगत सीमाओं से कहीं ऊपर था। यही कारण था कि
रहे। सचमुच वे अजातशत्रु थे। धुर विरोधी भी उनसे
एक पुलिसकर्मी से उपराष्ट्रपति बन
संकल्प का प्रमाण है। वे राष्ट्रीय नेता होकर भी क
की मिट्टी ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा था। अतः
तलाश लेते थे। वे एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील
वे सुख-दुःख के साथी थे। हमने
पार किया। अनेक मुद्दों पर उनसे खुलकर बहस
मनुष्य थे। दोस्तों के दोस्त थे। उनकी इस संवेदनशी
को लागू कराने का सुअवसर दिया।
उनके निधन से भारतीय राजनीति
हमारे बीच से उठ गया। भैरों सिंह जी की काया
में सदैव रहेगी। उनके उपराष्ट्रपति बनने पर मैंने कह
बन कर उभरी है। आज वही चंदन का तिलक फि
उनका बिछोह मेरे लिए असहनीय
मित्र की अंतिम विदाई के लिए शब्द नहीं हैं। मैं स
कह सकता हूँ कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान
असहनीय दुःख सहने की शक्ति दें।

नई दिल्ली
15 मई 2010

6A, Krishna Menon Marg, N
Tel.: +91 11 23015308, 2379383

म विदाई

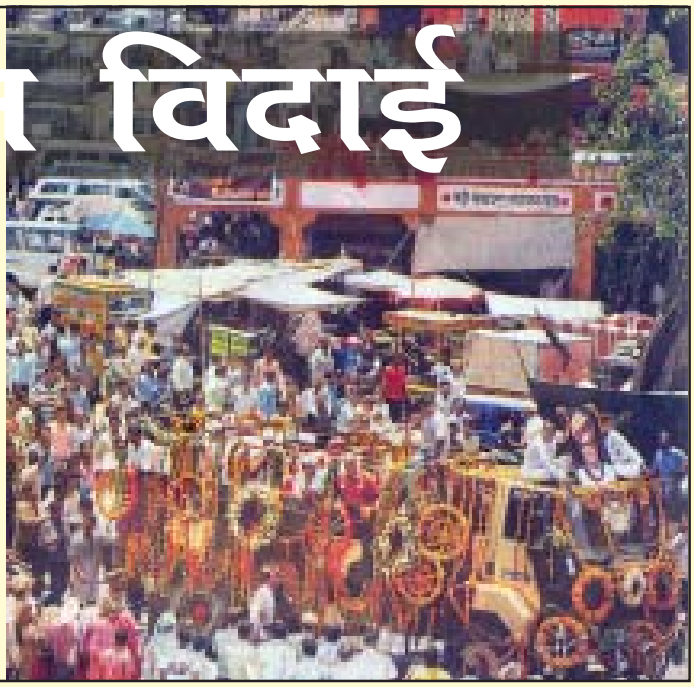

के अलावा बड़ी संख्या में लोग ने पुष्प अर्पित कर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। यहां से निकला अंतिम यात्रा का काफिला चांदपोल से होता हुआ पानीपेच के लिए रवाना हुआ। रास्ते में सैकड़ों लोगों ने बाबो सा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अम्बाबाड़ी स्थित महाराव शेखा सर्किल पर करीब 10 मिनट तक पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करने का सिलसिला चला। बड़ी संख्या में एकत्रित राजपूत समाज के लोगों ने अपने प्रिय नेता को नमन किया। भवानी निकेतन परिसर में बने सवाई मानसिंह द्वार पर समाज बंधुओं ने द्वार से पुष्पवर्षा की। ■

बिहारी वाजपेयी

शोक संदेश

निधन से एक घनिष्ठ मित्र, वैचारिक सहयोगी, वरिष्ठ
सपूत हमारे बीच से चला गया।
और बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में हमसफर
। वे पार्टी के जरूर थे मगर उनका व्यक्तित्व और सम्पर्क
था कि वे राजस्थान में तीन बार सरकार चलाने में सफल
उनसे अपने मन की बात खुलकर कर लिया करते थे।
पति बनने का उनका सफर उनके परिश्रम और उनकी दृढ़
भी कभी अपनी मिट्टी और जड़ों को नहीं भूले। राजस्थान
अतः वे अभावों और अन्तर्विरोधों में भी समन्वय का रास्ता
दनशील राजनीतिज्ञ और अच्छे मित्र थे।
हमने साथ-साथ राजनीति के कई संघर्षों और पड़ावों को
बहस होती थी। अंततः मैंने पाया कि वे एक संवेदनशील
विदनशीलता ने ही 1977 में उन्हें अंत्योदय जैसे कार्यक्रम

नीति के एक युग का अवसान हो गया है। एक जननायक
गया हमारे बीच नहीं रही मगर उनकी माया हमारी स्मृतियों
ने कहा था कि 'मिट्टी की धूल माथे पर चंदन का तिलक
क फिर से अपनी माटी में मिल गया है।
हनीय है। उनके निधन पर मैं आहत हूं। मेरे पास अपने
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं। मगर इतना तो
ते प्रदान करे तथा हम सभी परिजनों और पार्टीजनों को यह

Marg, New Delhi 110011 India
23793877 Fax: +91 11 23794612

भावुक हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता

आडवाणी बोले मैंने राजनीति यहीं से शुरू की, लेकिन आज जिस प्रसंग में आया वह बहुत कष्टदायक... शेखावतजी की लगाई नींव पर खड़े हैं हम–गडकरी

पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने जयपुर आए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पुरानी यादों में खोकर भावुक हो उठे। होटल खासा कोठी में भाजपा के नेता एकत्र रहे जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की और पुराने संस्मरण भी सुनाए। पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी बोले, आज जिस प्रसंग में वे जयपुर आए हैं वह बहुत कष्टदायक है। शेखावत के साथ की सारी स्मृतियां सजीव हो उठी हैं। मैंने राजनीति यहीं से शुरू की। 1947 से 57 तक 10 साल राजस्थान में गुजारे और इसी दौरान 1951 में जनसंघ का जन्म हुआ। 1952 के चुनाव में शेखावत जनसंघ से विधायक बने। बाद में तीन बार मुख्यमंत्री और उप राष्ट्रपति बने। पहले भाजपा राजस्थान व मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में ही सत्ता

में आ पाई थी। उन्होंने शेखावत को सुशासन, जनकल्याण और विकास की कल्पना करने वाला पहला नेता करार दिया। श्री आडवाणी ने बताया कि भैरोंसिंह के भाई स्व. बिशनसिंह शेखावत उन दिनों संघ की शाखा में आते थे और 1952 में उन्होंने ही उम्मीदवारी के लिए नाम सुझाया। उन्होंने ही मिलवाया, इसके बाद भैरोंसिंह को उम्मीदवार बना दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पुरानी मुलाकातें याद करते हुए कहा कि आज पार्टी रूपी जो इमारत खड़ी है, शेखावत उसके आधार स्तम्भ थे। उन जैसे कार्यकर्ताओं ने ही परिश्रम कर पार्टी की नींव डाली थी जिस पर आज हम खड़े हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि देश ने कद्दावर नेता, पार्टी ने वरिष्ठतम कार्यकर्ता और मैंने पिता तुल्य नेता खो दिया। मुझे हमेशा बेटी की तरह माना। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भी एक वाकिया याद करते हुए बोलीं, जब 1985 में मैं पहली बार विधायक बनकर आई तब बहुत डरी हुई थी कि विधानसभा में कैसे बोलूं। मुझे अंग्रेजी ही आती थी, हिन्दी बहुत कम बोल पाती थी, लेकिन शेखावत ने अंग्रेजी में बोलने की इजाजत नहीं दी। इस पर मैंने दो रात हिन्दी बोलने का अभ्यास किया तब जाकर सदन में बोल पाई। शेखावत ने इसके लिए शाबाशी दी और मुझसे लड्डू मंगवाए। ■

शेखावतजी को श्रद्धांजलि

शेखावत एक महान नेता थे जिन्होंने देश की एकता बनाए रखने के लिए काम किया। **- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति भारत**

शेखावत की सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जनता की पूरी निष्ठा से सेवा की।

-डॉ. हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति भारत

शेखावत के निधन से मुझे निजी क्षति हुई है और मैंने एक पितृतुल्य व्यक्ति को खोया है। **-सुषमा स्वराज, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता**

भैरों सिंह शेखावत के निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक और संसदविद् खो दिया है। **-सोमनाथ चटर्जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष**

भैरोंसिंह शेखावत ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान जनता की निःस्वार्थ भाव से सेवा की। **-मायावती, मुख्यमंत्री उ.प्र.**

वह चाहे विपक्ष में रहे या सरकार में, उन्होंने हर समय जो अपनापन दिखाया, वह राजनीति में कम ही देखने को मिलता है।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान

शेखावत का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि वह भाजपा में रहते हुए भी विपक्ष के नेताओं के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखते थे।

-मुलायम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उ.प्र.

शेखावत प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह विपक्ष की राजनीति में अग्रणी रहे और राजनीति में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। **-शरद यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री**

शेखावत मेरे पिता के समान थे, यह मेरी निजी क्षति है। वह देश की राजनीति में स्वाभिमान और ईमानदारी के पुरोधा थे।

-उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री म.प्र.

शेखावत बहुत नेकदिल व्यक्ति थे और सभी राजनीतिक दलों में उनकी दोस्ती थी। उनका निधन देश के लिए क्षति है।

-फारुक अब्दुल्ला, केन्द्रीय मंत्री

पितातुल्य थे शेखावतजी : नितिन गडकरी

हमने भारत माता के महान सपूत, एक उत्कृष्ट राजनेता, कुशल प्रशासक और लोकनेता श्री भैरों सिंह शेखावत को खो दिया है। श्री भैरों सिंह जी के निधन से देश को और भाजपा को भारी क्षति हुई है। श्री शेखावत हमारी पार्टी के पहली पीढ़ी के नेता थे, उन्होंने जनसंघ और फिर भाजपा को देश की एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाई। श्री शेखावत ने जनसंघ तथा भाजपा में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया और बाद में अपने उत्तम कार्यों की वजह से वे देश के उप–राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए।

उन्होंने अर्धशतक से भी ज्यादा समय तक पार्टी की सेवा की और कभी पार्टी की विचारधारा के साथ समझौता नही किया। उनकी कर्मठता से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पहला मुख्यमंत्री मिला और उन्होंने श्री दीनदयाल जी के अंत्योदय की योजना को कड़ाई से अपने कार्यकाल में लागू कर अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता की। वे अपने जुझारूपन और कर्मठता के कारण राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री बने और पार्टी को उनके प्रशासनिक कार्यक्षमता पर हमेशा गर्व रहा।

मेरे जैसे भाजपा कार्यकर्ता के लिए श्री शेखावत जी पितातुल्य थे। उनके निधन से हमने एक मार्गदर्शक खोया है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी चिरशांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।■

अरुण जेटली, नेता विपक्ष, राज्यसभा

श्री शेखावत देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उनके निधन पर हम सबको गहरा दुख है। श्री शेखावत राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और अपनी कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें भारत का उप–राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। श्री शेखावत बहुत बडे समाज सुधारक थे। उन्होंने पूरे देश में सतीप्रथा को समाप्त किया। वे स्वच्छ आचरण के धनी थे। वे व्यक्तिगत सम्बंधों को राजनीति से ऊपर रखते थे। उनके निधन से पार्टी को गहरा आघात पहुंचा है। उनके प्रति मैं श्रंद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

श्री शेखावत जी के निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। श्री शेखावत बहुत ही कर्मठ, जुझारू और ईमानदार राजनेता थे। अपनी लगन और परिश्रम के द्वारा वे एक आम कार्यकर्ता से देश के उप–राष्ट्रपति बने। वे जनसंघ से लेकर अपने अन्तिम समय तक पार्टी के प्रति समर्पित रहे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा

श्री शेखावत जी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है। श्री शेखावत मेरे लिए पितातुल्य थे। मैंने अपना राजनीतिक जीवन उन्हीं के मार्गदर्शन में शुरू किया और उन्हीं के राजनीतिक जीवन से प्ररेणा लेकर अनेकों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। श्री शेखावत पार्टी के समर्पित और निष्ठावान, अनुशासनप्रिय नेता थे। उनके जाने से मुझे और पार्टी को बहुत भारी क्षति हुई है।

भगत सिंह कोश्यारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा

सांसद राज्यसभा एवं भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भगत सिंह कोश्यारी ने श्री शेखावत के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है और अपनी भावभीनी श्रृंद्धाजलि अर्पित की है।

हर दल में थे मित्र

भैरों सिंह शेखावत भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत थे, जिनके हर राजनीतिक दल में मित्र थे। गठबंधन के इस दौर में विरोधियों को भी अपना बनाने की कला में उनका कोई सानी नहीं था।

अपने पचास वर्ष से अधिक के राजनीतिक जीवन में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा, जहां उनके मित्र न हों। अपने प्रशंसकों में 'भैरों बाबा' के नाम से मशहूर शेखावत की राजनीतिक सोच दलगत राजनीति से ऊपर थी। 83 वर्ष की आयु में पेरिस के एफिल टावर पर चढ़ना उनकी अदम्य राजनीतिक इच्छाशक्ति का नायाब उदाहरण है। वह उम्र को कैरियर में बाधा नहीं मानते थे।

1952 से वर्ष 2002 तक एक बार को छोड़कर लगातार विधानसभा का चुनाव जीतने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। ■

एम. वैंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

हमारे वयोवृद्ध नेता श्री भैरोसिंह शेखावत के निधन पर हार्दिक दुःख हुआ है। वे अत्यंत कुशाग्र एवं लोकप्रिय नेता थे। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान दूरद्रष्टा और कुशल नेता को गंवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक अपूरणीय हानि है क्योंकि वे सदैव हमारे कुशल संस्थापक और मार्गदर्शी बने रहे थे। वे अत्यंत दयालु और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। इसीलिए वे दलगत नीति से ऊपर उठ कर सदा ही संसद में सबके प्रशासक बने हुए थे।

राजस्थान के लोगों ने उन्हें तीन कार्यकालों तक उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखा था और वे सदैव उनकी सेवाओं को याद करते रहेंगे। निःसंदेह, वे आज तक राज्य में विराजमान सभी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ रहे थे। वे सचमुच जननायक थे जिन्होंने निरंतर अविच्छिन्न रूप से गरीबों तथा दलितों की सेवा का कार्य किया। उन्होंने सदा ही गरीबों की समृद्धि के लिए नीतियां चलाते हुए ऐसे कार्य किए जिनसे उनकी भलाई के लिए नूतन नीतियों और विकास योजनाएं फलती फूलती रहें। उन्हें भारत का रॉकफेलर माना जाता था और इसीलिए गरीबों में सबसे आखिरी गरीब के लिए अन्त्योदय योजना चला कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। वे गरीब परिवार वाली पृष्ठभूमि और जमीनी राजनीति से उभरते हुए भारत के 11वें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे। राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़े गरिमापूर्ण और समीचीन ढंग से चलाया था। उन्होंने सदन के कामकाज के संचालन में उत्कृष्टता और निष्पक्षता की अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने स्नेही स्वभाव, बेबाक ईमानदारी और सहमति की राजनीति के अनुपालन से अपने पद की गरिमा में चार चांद लगा दिए थे। ■

व्यावहारिक और सिद्धांतवादी राजनेता थे भैरोंसिंह शेखावत

v#.k tsVyh

Iर्वगुण सम्पन्न राजनेताओं को कभी भी उनके पदों की हैसियत से नहीं जाना जाता है बल्कि वे अपने पीछे जो अमिट छाप छोड़ जाते हैं, उन्हीं से उनकी पहचान होती है। निःसंदेह, भैरों सिंह उन व्यक्तियों में से एक थे जिनकी अमिट छाप ने उन्हें भारत का सर्वोत्कृष्ट राजनीतिज्ञ बना दिया।

वह निर्धन परिवार से आए थे। वे पुलिस इंस्पेक्टर थे जब उनसे भारतीय जनसंघ ने 1952 में आम चुनाव लड़ने के लिए कहा था; उन्होंने अपना यह प्रथम चुनाव जीता और राजस्थान की राजनीति पर पांच दशकों तक अपना सिक्का जमाए रखा।

बहुत कम ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ मिलेंगे जो उनके आकर्षक व्यक्तित्व का सामना भी कर पाएं। अपने मित्रों का हृदय जीतने की उनकी कुशलता का तो जवाब ही नहीं था। वह जनसंघ के प्रति और फिर भाजपा के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ रहे, परन्तु उनके मित्रों का नेटवर्क तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर छाया हुआ था।

जितना वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सान्निध्य में सुख प्राप्त करते थे, उतना ही आनन्द उन्हें श्री चन्द्रशेखर के साथ रह कर भी महसूस होता था।

अपने आखिरी दौर में उन्होंने राज्यसभा का की अध्यक्षता की। एक साधारण शैक्षिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति होते हुए भी उन विद्वान व्यक्तियों से भी कहीं बढ़ चढ़ कर सदन संचालन का काम किया करते थे। सदस्यों के साथ उनकी व्यक्तिगत घनिष्ठता, उनका व्यंग्य, हास्य और सहनशीलता ने उन्हें सदा और भी बल प्रदान किया। यदि सदन के दो सदस्य पड़ जाते थे तो वे उन दोनों सदस्यों को बोलने का

भैरोंसिंह उन व्यक्तियों में से एक थे जिनकी अमिट छाप ने उन्हें भारत का सर्वोत्कृष्ट राजनीतिज्ञ बना दिया।

मौका दे देते थे और इस प्रकार जहां ऐसा लगता था कि अब तो सदन को स्थगित करना ही पड़ेगा, परन्तु वह स्थगन टल जाता था। वह चर्चा के दौरान पूर्ण काल में या तो चेयरमैन की सीट पर बैठे रहते थे या अपने चैम्बर से बहस सुना करते थे। राज्य सभा के सभापति के तौर पर उन्होंने अपने दलगतविहीन रवैये के कारण स्ट्टेसमैन बनकर स्वयं को पार्टी गतिविधियों से दूर रखा।

वे किस प्रकार से पांच–छह दशकों तक राजनीति करते रहे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते ही रहे? यह उनका जन नेतृत्व संगठन का समर्थन तो था ही, परन्तु इसके साथ ही उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता की पूंजी भी जुड़ी थी। यहां तक कि उनके विरोधी भी कभी उन पर निष्पक्ष होने का दोष नहीं मढ़ सके। उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा को स्तर को बहुत ऊंचाई पर बनाए रखा और कभी भी किसी निंदनीय विवाद का शिकार नहीं बने।

उनके व्यक्तित्व की एक और गरिमा भी थी कि वे समयानुकूल कार्य करते थे और सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाते थे। वे पहली बार 1952 में राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित हुए थे और उनके साथ जनसंघ के 10 अन्य विधानसभा सदस्य चुने गए थे। विधानसभा के प्रथम कार्यकाल में जागीरदारी खत्म करने का कानून पेश किया गया था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय ने सही सम्मति देते हुए जनसंघ ने जागीरदारी समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन करने का निर्णय लिया था।

किन्तु, लगभग शेष सभी अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिंह ही केवल जनसंघ के एकमात्र सदस्य बचे रहे थे जिन्होंने जागीरदारी समाप्त करने का समर्थन किया था। यह भी ऐसी स्थिति में था जब स्वयं उनके अपने

समुदाय के लोगों का इस प्रस्ताव पर समर्थन नहीं था।

इसी प्रकार, सती प्रथा के प्रति भी उनके समुदाय के कुछ ही लोगों के समर्थन के बावजूद भी वे ही इस घोर घृणित प्रथा के खिलाफ डटकर खड़े हो गए थे। ऐसे अवसरों पर उन्होंने कभी भी वोट बैंक राजनीति का विचार तक नहीं किया और उन्होंने अपने राजनीतिक गतिविधियों के रूप में सामाजिक सुधारों को अपनाया।

उनकी सैद्धांतिक राजनीति, जन नेतृत्व, स्नेही व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के उच्चतम स्तर जैसे मिलेजुले तत्वों के कारण ही चुनावी पराजय के बाद भी फिर से उन्हें विजय दिलाने में मदद दी।

वह अनेक कार्यकालों तक विधायक रहे और अनेक अवसरों पर राजस्थान में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने तीन बार राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद संभाला और अन्ततः वह भारत के उप–राष्ट्रपति बने। राज्यसभा में उन्होंने प्रश्नकाल के समय अल्पकालीन पूरक प्रश्न पूछने की प्रथा शुरू की। उनके ही कार्यकाल में प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर वास्तव में दिया गया, जिसके कारण तात्कालिक चर्चा हो पाई। क्योंकि सभी प्रश्नों का उत्तर देने की संभावना बनी रहती थी, इसीलिए मंत्रियों को तैयार होकर आना पड़ता था। वह एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि नेतृत्व का दबाव उनके तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र के बीच बाधा बन सकता है। लगभग हर चुनाव में वे अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लेते थे क्योंकि उनके सिद्धांत उन्हें लोकप्रिय नहीं बनने देते थे। ऐसे थे भैरों सिंह जो व्यावहारिक परन्तु सिद्धांतवादी थे। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं।)

देश के संविधान, लोकतंत्र और व्यवस्था पर आंच नहीं आने दी जायेगी : प्रभात झा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा ने सीबीआई के राजनीतिकरण के विरोध में 12 मई को भोपाल के भवानी चौक प्रांगण में विशाल धरना, आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने के लिए आपातकाल लगाया था, तब जनसंघ ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया था। 19 माह जेलों में रहने के बाद भी हमारी चिंता देश में लोकतंत्र बहाल करने की थी। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार यदि सोचती है कि वह सीबीआई का राजनीतिकरण करके विपक्ष को भयाक्रांत कर सकती है, तो यह कांग्रेस की नासमझी है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान, लोकतंत्र और व्यवस्था पर आंच आना बर्दाश्त नहीं करेगी।

धरना, आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग, कप्तान सिंह सोलंकी, रामेश्वर शर्मा, सरिता देशपांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेसीकरण करके देश के सम्मान को मटियामेट कर रही है।

धरना, प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कैलाश जोशी ने कांग्रेस द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग किए जाने की बानगी बताते हुए कहा कि बोफोर्स तोप दलाली कांड के अभियुक्त क्वात्रोची दस जनपथ के करीबी थे, इसलिए क्वात्रोची को बचाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव और कटमोशन जैसे नाजूक समय में समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा सीबीआई का कटपुतली के रूप में इस्तेमाल किया। अनुपातहीन सपंत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और मायावती को तात्कालिक राहत पहुंचाकर समर्थन जुटाया। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।

प्रो.कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस यूपीए सरकार को बचाए रखने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। विरोधियों को फंसाने के लिए सीबीआई को हथियार बनाया जा रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग ने धरना, प्रदर्शन आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की गरिमा को ताक में रख दिया है।

वह अंक बल जुटाने के लिए किसी भी स्तर पर अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यवाही करने में जुटी है। ■

भैरोंसिंह शेखावत - एक दीपस्तंभ

';ke tkt

Ihkर के एक गरीब परिवार में जन्मे और देश के शिखर पर पहुंचे ऐसे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत जी, जिन्होंने 87 साल की जीवनयात्रा पूरी की इनका जीवन विविधता से परिपूर्ण व सदैव आम आदमी की चिंता करने वाले राजनेता का जीवन था। 1952 में राजकीय जीवन की उन्होंने शुरूआत की। दस बार विधानसभा, एक बार राज्यसभा, एक टर्म उपराष्ट्रपति यह उनका लेखा–जोखा है। तीन बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, सात बार नेता विपक्ष रहे। अपनी राजनीति का पूरा केन्द्र बिन्दु राजस्थान रखते हुए भी भारतीय जनसंघ और भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के त्रिमूर्ति में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ उनकी गणना होती थी।

अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने के पहले पुलिस डिपार्टमेंट में एक हवलदार के रूप में उनकी भूमिका थी। देश में भाजपा के पहले तीन मुख्यमंत्री 78 में आये थे जिसमें मध्यप्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी, हिमाचल में शांताकुमार जी व राजस्थान में भैरोंसिंह जी। राजस्थान में पार्टी को निर्विवाद बहुमत कभी प्राप्त नहीं हुआ पर पक्ष व विपक्ष के विधायकों का सहयोग लेकर राजस्थान की गद्दी पर भैरोंसिंह जी ने यशस्वी राजपात किया।

अपना शालेय शिक्षण पूर्ण करने के लिए उन्हें 18 कि.मी. पैदल चलना पड़ता था। इसी का परिणाम राजकाज में व पार्टी में जहां भी कुछ कहने का व करने का अवसर प्राप्त हुआ तो आम आदमी की भूमिका में जाकर सोचते थे और उसको क्रियान्वित करते थे।

2002 में जब वे उपराष्ट्रपति बनकर मौलाना आजाद रोड के निवास स्थान में स्थापित हुए तो सदैव अकेलापन महसूस करने वाली कोठी लोगों से भर–भरकर बहने लगी। वहां सदैव लोगों का रेला लगा रहता था। उपराष्ट्रपति पद के सारे प्रोटोकॉल के संकेत भंग करकर सामान्य आदमी उन्हें

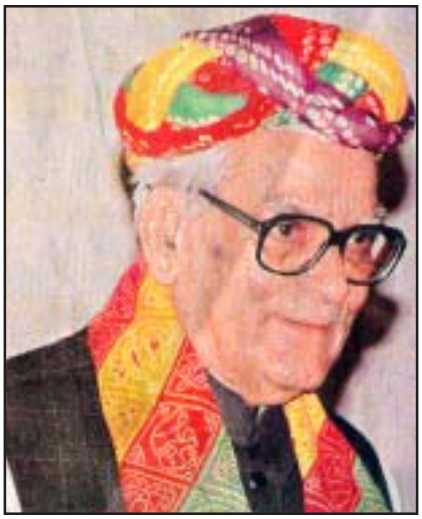

मिल सकता था और उसंकी सुनवाई भी होती थी। उनके उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अलग–अलग प्रकार के कार्यक्रम सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशिक्षणात्मक और प्रबोधन के, सम्मान के बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन वहां हर हफ्ते होता था।

अपनी दिलखुश शैली और बातूनी लहजे से उन्होंने काफी मित्र परिवार इकट्ठा किया था। उनकी मित्रता में पार्टी या विचारधारा का बंधन आड़े नहीं आता था। उनके अनेक प्रशंसक विविध राजकीय पक्षों में सक्रिय मिलते हैं। तीन–तीन बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल यशस्विता से निभानेवाले इस महारथी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या नैतिकता के आचरण के आरोप लगाने की हिम्मत उनके विरोधियों की भी नहीं हुई। ईमानदारी, सादगी, सहजता व सहिष्णुता का सुंदर मिलन भैरोंसिंह जी के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है।

1952 में जीतने के बाद तुरंत ही उनकी कर्मठता की झलक पहले ही कार्यकाल में देखने को मिली। जागीरदारी व सामंतशाही से संबंधित जो बिल राजस्थान में पेश किया गया था उसका विरोध करने का जिक्र भारतीय जनसंघ के एजेंडे में था। जनसंघ के 8 सदस्यों में से 6 सदस्यों को इस बिल का विरोध ना करने से पार्टी से निष्कासित करना पड़ा पर भैरोंसिंह जी अपनी भूमिका पर डटकर खड़े रहे। इसी प्रकार राजस्थान में चल रही सती प्रथा के खिला भी अपने राजपूत समाज के खिलाफ खड़ा रहना पड़ा। वोट बैंक पॉलिटिक्स की ओर ना देखकर उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भूमिका ली। मेरी मां ने ही मेरा भरण–पोषण किया है, मेरी 18 साल की आयु में मेरे पिताजी गुजर गये यदि माता जी सती प्रथा में बलि हो जाती तो मैं भी आपके सामने नहीं होता ऐसा दो टूक जवाब देकर ताकत के साथ वो इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े हुये।

दिल्ली में पश्चिम विहार स्थित एक्शन ग्रुप के बालाजी अस्पताल के उद्घाटन का निमंत्रण देने हेतु सभी संचालक व ट्रस्टीज को लेकर मैं उपराष्ट्रपति भवन पहुंचा। निमंत्रण स्वीकार करने के पहले उन्होंने मुझे देखकर कहा– ''श्याम ये सभी लोगों को लेकर तू आया तो है पर उद्घाटन के बाद तू पार्टी दफ्तर से कोई गरीब

पेशेंट को एडमिट करने को कहेगा या किसी के बिल में राहत देने को कहेगा तो ये लोग मानेंगे क्या?'' आखिर संचालक लोगों द्वारा गरीबों के लिए अलग व्यवस्था व अस्पताल की फीस में राहत की स्कीम का ऐलान करने के बाद ही उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और कार्यक्रम में उसकी घोषणा की। 'आम आदमी' यह उनका निरंतर चिंतन का विषय रहता था। इसके ही परिणामस्वरूप पंडित दीनदयालजी की 'अंत्योदय' कल्पना का प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वयन उन्होंने अपनी सरकार में शुरू किया।

उपराष्ट्रपति जैसे बड़े ओहदे को संभालते हुए भी अपने पुराने सहयोगी व मित्रों को वो कभी नहीं भूले। पद के संकेतों के कारण राजनीतिक पार्टी की सदस्यता खत्म होते हुए भी पुराने प्रचारक व नेता जो वयोवृद्धता के कारण बीमार थे ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे, जगदीश प्रसाद जी माथुर, कैलाशपति मिश्रा, प्यारेलालजी खंडेलवाल इन सबकों देखने व उनका इलाज करवाने के लिए पूरे डाक्टर मित्रों के साथ पार्टी दफ्तर आने में उन्होंने संकोच नहीं किया। खुद की हाजिरी में उनका पूरा चैकअप उन्होंने करवाया और स्वास्थ्य की चिंता की यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक स्वर्गीय गोलवलकर गुरूजी के जन्मशताब्दी कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति जी जायेंगे या नहीं इसकी काफी चर्चा अखबारों में रही। वो वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक समरसता के प्रबोधन व गतिविधियों को समर्पित किया था। बगैर हिचकिचाहट स्वयंसेवक कहलाने वाले उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह जी गुरूजी जन्मशताब्दी के समापन कार्यक्रम में पहुंच गये। वहां पर उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ–साथ गरीबी व अशिक्षा के भी आह्वानों पर ध्यान दिलाया। संघ को इस विषय पर भी काम करना चाहिए ऐसा आग्रहपूर्वक प्रतिपादित किया।

विधानसभा व राज्यसभा के कामकाज का संचालन करते समय अपनी विशिष्ट शैली से कुशल विनोदबुद्धि से काम चलाकर उन्होंने अपने संपन्न व्यक्तित्व का परिचय दिया है अपने से मतभिन्नता रखने वाले मित्रों को भी वह कुशलता से अपना बना लेते थे। अपने प्रदीर्घ अनुभव व व्यक्तित्व के कारण ही राज्यसभा के सभापति पद पर बैठकर उन्होंने जो मानदंड प्रस्थापित किये उसे आने वाली पीढ़ी जरूर याद करेगी। सभी तारांकित सवालों के जवाब सरकार द्वारा दिया जाना आवश्यक कर, प्रश्नकाल किसी भी इश्यू पर खंडित न करने का संकेत उन्होंने प्रस्थापित किया। सदन में चलने वाले काम देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है उसकी गरिमा रखनी चाहिए। यह उन्होंने बताया।

विधानसभा व राज्यसभा के कामकाज का संचालन करते समय अपनी विशिष्ट शैली से कुशल विनोदबुद्धि से काम चलाकर उन्होंने अपने संपन्न व्यक्तित्व का परिचय दिया है अपने से मतभिन्नता रखने वाले मित्रों को भी वह कुशलता से अपना बना लेते थे। अपने प्रदीर्घ अनुभव व व्यक्तित्व के कारण ही राज्यसभा के सभापति पद पर बैठकर उन्होंने जो मानदंड प्रस्थापित किये उसे आने वाली पीढ़ी जरूर याद करेगी।

व्यवहार में स्वदेशी व स्वभाषा ये विषयों में भी वो आग्रही रहते थे। सार्वजनिक जीवन में सदैव वो धोती, कुर्ता और ऊपर जैकेट या कोट में ही दिखते थे। देश में छोटे–मोटे प्रसंगों में भी अंग्रेजी में बोलना यह शान समझने वाले नेताओं को भी उन्होंने बता दिया की उपराष्ट्रपति के ओहदे पर रहते हुए पूर्व यूरोप में जब वो प्रवास पर गये उन्होंने अपने देश की भूमिका हिंदी में ही रखी।

मुझे माननीय आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, अरूण जेटली जी, नजमा हेपतुल्ला जी, माननीय मदनदास देवी जी के साथ भैरोंसिंह जी के अंत्यदर्शन हेतु जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां अपार जनसमुदाय के साथ–साथ सभी दलों व विचारधारा के मंत्रियों का जमावड़ा मैंने देखा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, शिवराज पाटिल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी, राजस्थान के गवर्नर, भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, महामंत्री रामलाल जी, अनंत कुमार जी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, प्रकाशसिंह बादल जी, रमण सिंह जी, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, निशंक जी सभी वहां सशरीर उपस्थित थे। अनेकों ने संदेश भिजवाएं।

राजस्थान के ढाणी ढाणीनक, गांव कस्बों में अपने विचार, राष्ट्रवाद के विचार पहुंचाने वाले कृतत्ववान व निगर्वी दीपस्तंभ को मैं शतशः वंदन कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। ■

(लेखक भाजपा केन्द्रीय कार्यालय के मुख्यालय प्रभारी हैं)

उन जैसा न कोई जुड़ पाएगा

pinu fe=k

उब्बे के दशक में मैं एक काम के सिलसिले में जयपुर आया था। जयपुर जाऊं और राजस्थान के सबसे बड़े नेता भैरोंसिंह शेखावत से न मिलूं, यह नामुमकिन था। वह उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। मैंने मुलाकात के लिए उनके कार्यालय फोन किया। वहां से जवाब मिला कि भैरोंसिंह अंडरग्राउंड हैं। मैं हतप्रभ रह गया कि कोई मुख्यमंत्री अज्ञातवास में कैसे रह सकता है। मैंने मुलाकात के लिए उनके करीबी एक पत्रकार मित्र को फोन किया। कुछ घंटे बाद ही पत्रकार मित्र का फोन आया कि वह मुझे लेने आएगा। मुलाकात कहां होगी, यह उसने नहीं बताया। मेरे मित्र ने मुझे जयपुर के सिविल लाइंस स्थित सरकारी बंगले पर उतार दिया। यह बंगला मुख्यमंत्री आवास से ज्यादा दूर नहीं था। सुरक्षा के लिए केवल एक सुरक्षाकर्मी था। मुझे उनके बेडरूम तक ले जाया गया। पूरे बंगले में अंधेरा था। जब मैंने उनसे इस मुद्दें पर चिन्ता जताई, तो उनका उत्तर उनके चारित्रिक दृढ़ता का प्रतीक था। वहां वे निर्द्वन्द्व होकर तत्कालीन राजनीतिक हलचलों का आकलन कर रहे थे।

असल में उन दिनों वह कुछ नियुक्तियों को लेकर भाजपा के कुछ दिग्गजों का दबाव झेल रहे थे। इसलिए उन्होंने अज्ञातवास का निश्चय किया था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे कुछ दिनों में प्रकट हो जाएंगे। हम लोगों ने लगभग दो–ढाई घंटे तक राजस्थान के इतिहास, राजनीति और मीडिया के रुख पर चर्चा की। उनके जवाब सारगर्भित थे। उनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा था।

वे जमीन से उठे हुए नेता थे। उनके राजनीतिक आकलन बहुत ही सटीक हुआ करते थे। उन्हें भलीभांति मालूम था कि वे कब जीतने जा रहे हैं और पराजय कब अवश्यम्भावी है। उनका आकलन पहली बार तब गलत साबित हुआ, जब उन्होंने सभी की सलाह दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का निश्चय किया।

हम लोगों ने लगभग दो–ढाई घंटे तक राजस्थान के इतिहास, राजनीति और मीडिया के रुख पर चर्चा की। उनके जवाब सारगर्भित थे। उनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा था।

वे जमीन से उठे हुए नेता थे। उनके राजनीतिक आकलन बहुत ही सटीक हुआ करते थे। उन्हें भलीभांति मालूम था कि वे कब जीतने जा रहे हैं और पराजय कब अवश्यम्भावी है।

उन्हें उन लोगों से भारी आघात लगा, जो लोग दिल्ली में मौलाना आजाद रोड स्थित उपराष्ट्रपति भवन जाकर उनका पैर छूते थे और मतदान के दिन उनके विरोध में मतदान किया। हममें से कुछ लोग अकसर उन्हें चेताया भी करते थे, लेकिन एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के बावजूद वे कई मायनों में एक ऐसे सीधे–सादे इंसान थे, जिनके लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा की तुलना में सम्मान और जुबान का ज्यादा महत्व था। मुझे नहीं मालूम कि वे मुझे इतना प्यार क्यों करते थे, जबकि मेरे उनके बीच न केवल पीढ़ी, बल्कि सांस्कृतिक अंतर भी था। वह रुढ़िवादी परिवार से आते थे।

वे सभी का विश्वास कर लेते थे चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। राज्यसभा के सभापति के रूप में वे सौम्य थे। युवा सदस्यों के लिए वे अंकल जी भी थे। वे शोरगुल या हंगामे के विरोधी थे। उन्होंने अपनी आवाज को कभी तीखापन नहीं दिया था। वे सबसे बात करते थे। वे हर विषय पर बात कर सकते थे। कितनी ऐसी हस्तियां होंगी, जो उनकी तरह पद से अलग व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड़ने का दावा कर सकती हैं? पिछले 25 दिसम्बर को अटल जी के घर मेरी भैरोंसिंह जी से मुलाकात हुई, जो अंतिम साबित हुई। लौटते समय मैंने उनके जबड़े पर प्लास्टर का पैबन्द देखा। जब वे अपनी हथेली पर गुटका रख रहे थे, तब मैंने दखल देते हुए कहा, 'अब तो इसको छोड़ दीजिए।'

वह अपने अंदाज में हंसे और बोले, 'अब छोड़कर क्या करना? पच्चासी पार कर गए। चल फिर रहा हूं, इसको छोड़ने से क्या उमर बहुत लम्बी हो जाएगी? करना क्या उमर को और लम्बी करके?' उन्होंने पूरी शान से जीवन बिताया। भावी पीढ़ियां उन्हें छपे हुए शब्दों व टीवी फुटेज से जानेंगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने हाड़–मांस का ऐसा मानव देखा। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राज्यसभा सांसद हैं)

...पृष्ठ 14 का शेष

सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उन्हें केवल खतरा मानते हैं और सबसे बड़ा शब्दों का प्रयोग करने से साफ इनकार करते हैं। इस पर हैरत नहीं कि दंतेवाड़ा कांड के बाद नक्सलियों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। शायद वे यह अच्छी तरह जान गए हैं कि कांग्रेसी नेता चिदंबरम के हाथ बांधे रखने पर आमादा हैं।

मनमोहन सिंह अपने पिछले और वर्तमान कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लगता यही है कि उनकी नाक के नीचे दलालों ने डेरा डाल रखा है। उदाहरण के लिए स्मरण करें भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष केतन देसाई का। सत्ता के गलियारों में पता नहीं, किस काम के कितने पैसे लगते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि घूस अब करोड़ों में ही ली जाती है। केंद्र सरकार चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार में तो नितांत असफल है ही, उसने प्रशासनिक सुधारों पर जानबूझकर रोक लगा रखी है। कोई भी यह बताने वाला नहीं कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट किसलिए धूल खा रही है। आतंकवाद से लड़ने के मामले में भी यह सरकार असफल ही अधिक है। इसमें संदेह नहीं कि मनमोहन सिंह विनम्र और विद्वान छवि से लैस प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस पर संदेह ही संदेह है कि इससे देश को क्या लाभ मिला है? हो सकता है कि 2009 के आम चुनाव में जनता के सामने कांग्रेस को फिर से मौका देने के अलावा और कोई उपाय न रहा हो, लेकिन देश को इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। संप्रग सरकार जिस तरह से चल रही है उस तरह से दस–बीस साल और भी चलती रहे तो देश का कल्याण होने वाला नहीं है। ■

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

नाकारेपन का नतीजा

यदि बेलगाम और खूंखार नक्सली छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 20 विशेष पुलिस अधिकारियों समेत 50 से अधिक लोगों को मारने में सफल रहे तो इसके लिए राज्य सरकार से अधिक केंद्रीय सत्ता जिम्मेदार है, क्योंकि वह नक्सलियों का मुकाबला करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। केंद्र सरकार की यह स्थिति दंतेवाड़ा कांड के बाद से खास तौर पर दिख रही है, जिसमें सीआरपीएफ के 75 जवान भेड़–बकरियों की तरह मार डाले गए थे। इस घटना के बाद स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद की जा रही था कि अब नक्सलियों के खिलाफ कोई कारगर अभियान नए सिरे से छेड़ा जाएगा। कम से कम इसकी अपेक्षा तो हर किसी को थी कि केंद्र और नक्सलवाद से ग्रस्त राज्य सरकारों की ओर से नक्सलियों पर इतना दबाव अवश्य बनाया जाएगा कि वे फिर कोई वारदात करने से बाज आएंगे। देश का दुर्भाग्य कि नक्सलियों पर कोई दबाव बनाने के बजाय केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को दबाव में ले लिया गया। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि यह काम किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेसी नेताओं की ओर से किया गया।

दंतेवाड़ा कांड के बाद आहत चिदंबरम को विपक्ष ने तो अपना समर्थन प्रदान किया, लेकिन खुद उनके दल के लोगों ने उनकी ऐसी घेरेबंदी की कि वह उसमें फंसकर रह गए। इसके दुष्परिणाम सामने हैं। देश को कुछ और सिपाहियों तथा आम लोगों की लाशें गिननी पड़ रही हैं। सच तो यह है कि दंतेवाड़ा कांड के बाद से नक्सली उत्पात मचाए हुए हैं और केंद्र सरकार आम सहमति, मध्यमार्ग आदि की तलाश में समय बर्बाद कर रही है। यह तलाश जिस तरह की जा रही है उससे यही साबित होता है कि न तो केंद्र सरकार नक्सलवाद से लड़ना चाहती है और न ही राज्य सरकारें।

नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वह कुछ करते रहने का दिखावा भर है। पहले मुर्गी आई या अंडा की तर्ज पर यह बेजा बहस की जा रही है कि पहले विकास किया जाए या फिर नक्सलवाद का खात्मा? यह बहस इस तथ्य से परिचित होने के बावजूद की जा रही है कि मौजूदा स्थितियों में नक्सली इलाकों में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना तो क्या, एक ईंट तक रखना मुश्किल है। क्या यह किसी को दिखता नहीं कि नक्सली किस तरह रेल पटरियां, स्कूल, टावर आदि ध्वस्त करने में लगे हुए हैं? नक्सलियों का मुकाबला करने से बचने के लिए कभी यह कहा जाता है कि वे अपने ही लोग हैं और कभी यह कि उनसे बात की जानी चाहिए। यह समझना मुश्किल है कि जो तत्व खुद प्रधानमंत्री के हिसाब से आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं उन्हें अपना भूला–भटका नागरिक बताने की होड़ क्यों मची है? क्या सीआरपीएफ के जवान किसी अन्य देश से आए थे? क्या गत दिवस जो लोग मौत की नींद सुला दिए गए वे किसी दूसरे ग्रह के थे? यह हास्यास्पद है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय नक्सलियों की यह कहकर निंदा कर रहा है कि उन्हें किसी ने भी निर्दोष लोगों की हत्याएं करने का लाइसेंस नहीं दिया है। सच्चाई यह है कि केंद्रीय सत्ता का नाकारापन नक्सलियों के लिए किसी लाइसेंस से कम नहीं।■

(साभार : जागरण)

नक्सलवाद पर रुख स्पष्ट करें प्रधानमंत्री : अरुण जेटली

नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) श्री अरुण जेटली द्वारा
18 मई 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

Hkkरतीय जनता पार्टी माओवादियों द्वारा कल दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में सिविलियनों तथा सुरक्षाकर्मियों पर किए गए नृशंस हमले की घोर भर्त्सना करती है। इस हमले ने इस दुखद वास्तविकता को पुनः पुष्ट किया है कि माओवादी देश के अनेक क्षेत्रों में प्रबलता प्राप्त करते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और सुरक्षा बलों के माओवादी प्रभाव वाले अलग–थलग पड़े क्षेत्रों को पुनः कब्जे में लेने के प्रयासों को निश्चित तौर पर अस्थायी धक्का पहुंचा है। भारत इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता कि माओवादी केवल गुमराह विचारकों का जमावड़ा है। वे एक हिंसक और नृशंस संगठन है, जो बल का प्रयोग करके भारत के संसदीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे भारत के संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर एक ऐसी वैचारिक निरंकुशता स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें शिष्टता, लोकतंत्र, संविधानवाद, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता तथा संवृद्धि के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां वैचारिक विमति के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। विरोधियों और असहमतों को समाप्त करने का ही कानून चलेगा।

ऐसी परिस्थितियों के तहत कोई भी, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध है, माओवादियों के विरूद्ध इस लड़ाई को कैसे कमजोर कर सकता है। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा इस मुद्दे पर जो बयान दिया गया, वह चिंता का कारण है। श्री चिदम्बरम एक घायल शहीद जैसे प्रतीत होते हैं। वे हतोत्साहित दिखाई पड़ते हैं। माओवादियों के अलग पड़े हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निश्चायक कदम उठाने के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में उनका जवाब था, ''सीमित अधिकारादेश के चलते मैं क्या कर सकता हूं।'' गृहमंत्री जी ने दावा किया था कि उनको इच्छानुसार व्यापक अधिकारादेश के विरूद्ध सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से केवल सीमित अधिकारादेश प्राप्त है।

भारत इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता कि माओवादी केवल गुमराह विचारकों का जमावड़ा है। वे एक हिंसक और नृशंस संगठन है, जो बल का प्रयोग करके भारत के संसदीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

माओवाद को समाप्त करने के लिए व्यापक अधिकारादेश देने की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की असमर्थता द्वारा माओवाद के विरूद्ध लड़ाई को कैसे पंगु किया जा सकता है? एक सीमित अधिकारादेश का वास्तविक अभिप्राय यह है कि हमारे सुरक्षा तंत्र को एक हाथ बाँधकर माओवादियों से लड़ना चाहिए। माओवाद के विरूद्ध आधी–अधूरी लड़ाई कभी कामयाब नहीं हो सकती। आधी–अधूरी लड़ाई हारी हुई लड़ाई होती है।

यह साजिश ही है कि जहां माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी रणनीति के प्रति प्रतिपक्ष पूर्ण समर्थन देने का इच्छुक है वहीं यह कांग्रेस पार्टी और संप्रग ही है, जो इस लड़ाई में देश के समूचे सुरक्षा तंत्र को हतोत्साहित करने में लिप्त हैं। ये हाशिए पर खड़े नेता नहीं है, जो माओवादियों के विरूद्ध नरम रवैया चाहते हैं। यह कांग्रेस पार्टी का केन्द्रस्थ नेतृत्व है, जिसने अब नरम रूख का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी की पत्रिका में प्रकाशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया हाल का पत्र माओवादियों के विरूद्ध नरम रूख रखे जाने का समर्थन करता है। माओवादियों से लड़ने के लिए बहुविध रवैया अपनाए जाने पर कहीं दो राय नहीं हैं। यदि अकेला विकास समस्या का समाधान कर सकता है तो समूचा राष्ट्र इसका स्वागत करेगा। किन्तु, माओवादियों के अलग–थलग प्रभाव वाले क्षेत्रों में विकास और गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले वहां सिविलियन प्रशासन को स्थापित करने के लिए प्रवेश करना होगा। वहां से हथियारों को सफाया करना होगा। इस ऑपरेशन के समर्थन में निश्चित ही सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होगी। जो कार्रवाई की बजाय टैम्पलेटों में विश्वास करते हैं वे वास्तविक बहस से मुँह चुरा सकते हैं। सर्वाधिक पिछड़े जिलों का विकास प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। किंतु, विकास केवल तभी हो सकता है, जब सरकार का इन क्षेत्रों पर नियंत्रण हो। इस समय ऐसा प्रतीत

होता है कि संप्रग सरकार सत्ता में तो हैं मगर उसका नियंत्रण नहीं है।

माओवादियों के विरूद्ध सुरक्षा की लड़ाई को कमजोर करने के बारे में ये सारे बयान संप्रग के सरकार से इतर राजनीतिक नेताओं से मिल रहे हैं। वे देश के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। वे केवल अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं। यह केवल भारत के प्रधानमंत्री ही है, जिनकी संसद तथा लोगों – दोनों के प्रति सांविधानिक जवाबदेही बनती है। इस मुद्दे पर सरकार की क्या स्थिति है? सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति सुरक्षा प्रहार करने से क्यों डरी हुई है? यह सही समय है, जब प्रधानमंत्री को खड़े होकर इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और राष्ट्र को बताना चाहिए कि इस विषय पर उनके क्या विचार है? क्या वे माओवादियों से लड़ने में सीमित अधिकारादेश के हामी है? क्या भारत माओवादियों के विरूद्ध आधी–अधूरी लड़ाई देखने जा रहा है या हम इस संकट के उन्मूलन के लिए अपने सारे राष्ट्रीय सुरक्षा संसाधनों का प्रयोग करेंगे?■

अफजल गुरु को फांसी न देने के खिलाफ दिल्ली प्रदेश का अभियान

दिल्ली प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की क्षमादान याचिका को दबाकर रखने पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को पानी की धार छोड़नी पड़ी। आतंकी अफजल गुरू की क्षमा याचिका पर टिप्पणी करने में दिल्ली सरकार ने चार साल लगा दिए। एक आतंकवादी के प्रति सरकार के इस रवैये के विरोध में दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जंतर–मंतर पर सभा तथा प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन कांग्रेस इस मामले में भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं ने आतंकवाद के मामले में वोटों की राजनीति करने पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस के इस कदम को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सभा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने संसद की ओर मार्च किया तो पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने बेरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए पानी की धार छोड़नी पड़ी। प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो ओमप्रकाश कोहली, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आतिफ रशीद, प्रदेश महामंत्री रमेश विधूड़ी, प्रवेश वर्मा, आरपी सिंह, सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा, आशीष सूद आदि भी उपस्थित थे। ■

अफजल मामला :

कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों की देशभक्ति पर प्रश्न खड़ा किया : नकवी

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि – दिल्ली सरकार द्वारा आतंकवादी अफजल की फांसी पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कह भारत के ''करोड़ों मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति'' को गाली दी गई है।

श्री नकवी ने नई दिल्ली स्थित संसद मार्ग पर अफजल को तत्काल फांसी दिये जाने की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा – अफजल गुरू एक आतंकवादी है, भारत में आतंकवादी हिंसा का जिम्मेदार है, देश के हिन्दू–मुसलमान सभी उसे तत्काल फांसी पर देखना चाहते है। श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस का यह कहना कि मुस्लिम इलाकों एवं कुछ अन्य स्थानों पर अफजल को फांसी से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मुसलमानों के देशप्रेम को संदेह के घेरे में खड़ा करने की कोशिश ही नहीं बल्कि आतंकवादी अफजल गुरू को बचाने का ''सुरक्षा–कवच'' बनाया जा रहा है। श्री नकवी ने कहा है कि आतंकवादियों को कड़ी सजा और देश की सुरक्षा, सभी देशवासियों जिसमें मुसलमान भी शामिल है, के दिल की राष्ट्रवादी आवाज है। अफजल गुरू आतंकवाद का प्रतीक है, इसको फांसी, आतंकवाद को फांसी होगी।

श्री नकवी ने कहा कि ''पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री'' है और उस आतंकवाद की फैक्ट्री से हर दिन अफजल गुरू और कसाब जैसे आतंकवादी का उत्पादन हो रहा है, इस आतंकवाद की फैक्ट्री को भी ध्वस्त करने का समय आ गया है।

श्री नकवी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दे रहा है, पर अमेरिका ने पाकिस्तान से कभी नहीं पूछा कि वह यह पैसा आतंकवाद से लड़ने में खर्च कर रहा है या आतंकवाद को बढ़ावा देने में। ■

घोटाले पर पर्दा

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए सीबीआई ने जिस तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मदद मांगी उससे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। वैसे तो इसकी पुष्टि 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से भी हो जाती है। इस नीलामी के जरिये सरकार को लगभग 70 हजार करोड़ रुपये हासिल हुए जबकि 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से बमुश्किल दो हजार करोड़ रुपये ही मिले।

यदि कोई वित्तीय मामलों का ज्ञाता न हो तो भी वह इस अंतर पर सवाल खड़े कर सकता है। 2जी स्पेक्ट्रम की मनमाने तरीके से हुई नीलामी केवल सवाल ही नहीं खड़े करती, बल्कि सरकारी खजाने को एक बड़ी धनराशि से वंचित भी करती है। बावजूद इसके केंद्र सरकार दूरसंचार मंत्री का बचाव करने में लगी हुई है। कांग्रेस की यह ⏭

साठ हजार करोड़ रुपए की हानि का जम्मेदार कौन?

भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 20 मई 2010 जारी प्रेस वक्तव्य

गत 19 मई 2010 को 3जी– स्पैक्ट्रम के आवंटन हेतु नीलामी संपन्न हुई। नीलामी से देश के सभी सर्किलों के वास्ते 67,710 करोड़ रूपए की राशि की वसूली हुई। नीलामियों में ऐसी प्रक्रिया आवश्यक रूप से शामिल होती है, जहां बाजार–तंत्र बेची जाने वाली परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत अवधारित करता है। स्पैक्ट्रम मूल्यवान राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। जब इसको उपयोगकर्ता या प्राइवेट पार्टियों के दोहन के लिए बेचा जाता है, तब सरकार को स्पैक्ट्रम की बाजारी कीमत अनिवार्यतः मिलनी ही चाहिए। 2जी स्पैक्ट्रम के आवंटन के पश्चात् जो राष्ट्रीय बहस शुरू हुई थी और गंभीर आरोप लगे थे, उनके कारण सरकार संचार मंत्री श्री राजा के प्राधिकार को कम करने के लिए, मूल्यों के अवधारण में विवेक का प्रयोग समाप्त करने के लिए और सारी प्रक्रिया के स्थान पर एक पारदर्शी नीलामी को स्थापित करने के लिए विवश हुई थी। ऐसे समय पर जब भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रिकार्ड ऊंचाई पर हो तब ऊंचे मूल्य की प्राप्ति अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह पोषित कर पाएगी। अब हमारे लिए चितां का प्रश्न यह है कि जब 3जी स्पैक्ट्रम से राजकोष को 67,710 करोड़ रूपए का अर्जन हो सकता है, तब 2007–08 में 2जी स्पैक्ट्रम को ऑल इंडिया लाइसेंस के वास्ते 1651 करोड़ रूपए के मूल्य पर क्यों आवंटित किया गया था। दूरसंचार मंत्री श्री ए. राजा का यह तर्क कि ''2जी और 3जी स्पैक्ट्रम के बीच वही अंतर है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल और बासमती चावल के बीच होता है'', आश्चर्य पैदा करने वाला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला चावल आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के बीच बांटा जाता है जबकि 2जी स्पैक्ट्रम रिलायंस कम्युनिकेशन्स, एयरटेल, वोडाफोन, स्वेन टेलकम, विडियोकोन, यूनीटेक आदि को आवंटित किया गया था। निश्चित ही ये समाज के दुर्बल वर्ग के लोग नहीं हैं, जिनको 2जी स्पैक्ट्रम के आवंटन के वास्ते राजा द्वारा दी गई इमदाद की जरूरत थी। 3जी स्पैक्ट्रम को इसकी उन्नत टैक्नोलॉजी के कारण आर्थिक रूप से और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। इसीलिए इसने उच्च मूल्य का अर्जन किया। इसके विरूद्ध 2जी स्पैक्ट्रम को व्यापक मूल्य इसलिए प्राप्त हुआ कि उसका उपयोग कहीं अधिक संख्या में लोगों द्वारा किया गया होगा। 3जी स्पैक्ट्रम का उच्च मूल्य उस अल्पमूल्यन की ओर संकेत करता है, जिस पर 2जी स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया था।

स्पष्टतः, 2जी स्पैक्ट्रम कौड़ी के मूल्य पर बेचा गया। दो आवंटियों ने स्पैक्ट्रम आवंटन पर तत्काल ही अपनी ईक्विटी कम कर दी थी। जिस लाइसेंस और स्पैक्ट्रम को उन्होंने 1651 रूप, में प्राप्त किया था, उसको ईक्विटी कम करने के वास्ते उन्होंने उससे 2 बिलियन डॉलर अर्थात् 9,000 करोड़ रूपए से अधिक राशि प्राप्त की। इस मूल्य पर 9 ऑल इंडिया लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इस मूल्य पर भी 60 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक की हानि हुई थी।

यदि 3जी स्पैक्ट्रम के मूल्यांकन में उच्च राजकोषीय घाटे को कुछ हद तक कम करने की संभाविता थी, तब राजकोषीय घाटा और कम हो सकता था यदि 2जी स्पैक्ट्रम के लिए भी इसी तरह नीलामी का तरीका अपनाया जाता।

श्री ए. राजा द्वारा अपने भ्रष्टाचार तथा भाई–भतीजावाद के कुकर्मों द्वारा राजकोष को भारी नुकसान पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री जी कब तक इसकी अनदेखी करते रहेंगे और कुछ भी गलत नहीं हुआ का बहाना बनाते रहेंगे?

⏭मजबूरी हो सकती है कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मंत्री का बचाव करे, लेकिन आम जनता के लिए ऐसे मंत्री असहनीय हैं।

यदि केंद्र सरकार को दूरसंचार मंत्री बहुत प्रिय हैं तो भी न्याय का यह तकाजा है कि जब तक उनके खिलाफ जांच जारी है तब तक उन्हें दूरसंचार मंत्रालय से बाहर रखा जाए। यह विचित्र है कि कांग्रेस ए.राजा का बचाव करने के लिए तथ्यों को तोड़ने–मरोड़ने में भी जुट गई है। कांग्रेस का ए राजा के बचाव में आगे आने का इसलिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीबीआई 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

यदि सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है तो फिर जांच किस बात की हो रही है? क्या कांग्रेस यह बताएगी कि सीबीआई ने दूरसंचार विभाग के अज्ञात अधिकारी समेत कुछ लोगों के खिलाफ सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का जो मामला दर्ज किया वह क्या था? कांग्रेस को यह भी पता होना चाहिए कि 2जी स्पेक्ट्रम के तौर–तरीकों को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग भी अपनी आपत्ति जता चुका है। निःसंदेह इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआई 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही है, क्योंकि यह जांच एजेंसी ऐसे मामलों में लीपापोती करने के लिए कुख्यात है।

अब तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए सीबीआई का जमकर दुरुपयोग कर रही है। मौजूदा राजनीतिक स्थितियों और साथ ही उच्च पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार के प्रति केंद्रीय सत्ता के ढुलमुल रवैये से इसकी आशंका अधिक है कि इस मामले में भी अंततः सच्चाई को दफन किया जाएगा। यह हास्यास्पद है कि एक ओर एक बड़े घोटाले पर पर्दा डाला जा रहा है और दूसरी ओर केंद्र सरकार की कथित उपलब्धियों का ढोल पीटा जा रहा है। चूंकि सरकार ऐसा करने के लिए स्वतंत्र भी है और समर्थ भी इसलिए कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह अहसास हो जाए तो अच्छा है कि वह अपनी प्रतिष्ठा खोती चली जा रही है। 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में मनमानी महज धनी और प्रभावशाली लोगों द्वारा किया जाने वाला बंदरबांट ही नहीं है, बल्कि आम जनता को केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाले यह संदेश भी है कि उसके शासन में भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण प्राप्त है। ■

सांसद सरोज पाण्डेय का नाम लिमका बुक ऑफ रिकार्डस् -२०१० में दर्ज

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने एक ही अवधि में त्रि–स्तरीय निवार्चित जनप्रतिनिधि बनने का एक अनोखा रिकार्ड बनाया है। उनका नाम एक ही अवधि (समय) में महापौर, विधायक एवं सांसद पद की निर्वाचित प्रतिनिधि के दायित्वों के निर्वहन हेतु लिमका बुक ऑफ रिकार्डस् –2010 में दर्ज किया गया है। राजनीति के इतिहास में यह प्रथम अवसर है, जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में देश की सर्वोच्च पंचायत, प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत एवं शहर की सर्वोच्च पंचायत पर एक साथ किसी जनप्रतिनिधि ने प्रतिनिधित्व किया हो। इस त्रि–स्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सफलतम दायित्वों के निर्वहन हेतु सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय जी का नाम राष्ट्रीय रिकार्ड – 2010 लिमका बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज किया गया है।

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सुश्री सरोज पाण्डेय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत छात्र राजनीति से प्रारम्भ की। विद्यार्थी काल में ही पण्डित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर की कुल सांसद के रूप में निर्वाचित होने का पहला अनुभव था। तब से लेकर आज तक निरन्तर विभिन्न पदों पर जैसे– अध्यक्ष, महिला महाविद्यालय सेक्टर 09 भिलाई,सदस्य जिला योजना मण्डल दुर्ग एवं कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, नगर पालिक निगम दुर्ग में 02 बार महापौर निर्वाचित हुई, जिसमें दूसरी बार में देश में सबसे अधिक मत प्रतिशत से जीतने वाले अभ्यर्थी (महापौर) का गौरव प्राप्त हुआ है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशालीनगर की विधायक , इसके पश्चात 15 वीं लोकसभा हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग लोकसभा से सांसद पद पर निर्वाचित हुई। आपने अपने राजनीति जीवन का प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रथम ईकाई से किया है तथा पार्टी की सेवा विभिन्न पदों पर पर रहते हुए की हैं यथा– महामंत्री, जिला महिला मोर्चा दुर्ग, सदस्य प्रदेश कार्यसमिति महिला मोर्चा, सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति युवा मोर्चा, दो बार प्रदेश महामंत्री भाजपा छत्तीसगढ़, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी 2008–2009। वर्तमान में भी आप भाजपा की राष्ट्रीय सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। ■

वेंकैया नायडू की पुस्तक 'टायरलेस वॉइस-रिलेंटलेस ज़र्नी' का विमोचन

gekj! l;oknnkrk }kjk

Jh वेंकैया नायडू की पुस्तक 'टायरलेस वॉइस–रिलेंटलेस ज़र्नी' उनके चुनिंदा भाषणों का संग्रह है जिसका विमोचन गणमान्य जनों की उपस्थिति में किया गया। इनमें विशेष रूप से भाजपा संसदीय पार्टी के चेयरमैन श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल एवं अन्य प्रतिष्ठित नेताओं और नागरिकों की उपस्थिति उल्लेखनीय है।

श्री एम. वेंकैया नायडू का चार दशकों का सार्वजनिक जीवन व निरंतर कठोर परिश्रम और संघर्ष तथा प्रेरणादायक रहा है। इसमें वे छात्र नेता, युवा नेता, विधान सभा के सदस्य, जन–प्रभावी नेता, भाजपा की राज्य ईकाई के अध्यक्ष, राज्य सभा के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा करते हुए चरमोन्मुखी व्यक्तित्व के धनी बने रहे। शिखर तक पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने राजनैतिक जीवन में अपनी विनम्रता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ समझौता नहीं किया और निरंतर अपने राजनैतिक चिंतन, स्पष्टवादिता, निर्भीकता, उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता और उससे भी अधिक देशभक्ति के महान मूल्यों का दामन नहीं छोड़ा। श्री वेंकैया की यह बड़ी भारी विशेषता है कि वे एक लाइन में भी इतना व्यंग्य और हास्य भर देते हैं जिसका लोगों के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे इससे आल्हादित होने के साथ–साथ मन में गहरी पैठ लेकर जाते हैं। श्री नायडू के निजी सहायक श्री सत्य कुमार, उनके मित्र श्री तिरूमला रंगाराव, श्री नेलामति रामनाथ और विशेष रूप से उनके जर्नलिस्ट मित्र श्री अप्पादासु कृष्णा राव ने इसके प्रकाशन में गहरा योगदान किया है। पुस्तक का प्रकाशन कालज्योति प्रोसेस प्रा. लि., हैदराबाद ने किया। इस पुस्तक की भूमिका के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार डा. इनगन्ती वेंकटा राव। ■

सखी मंच की बैठक

सखी मंच की सदस्य पार्टी छवि का निर्माण करें व सुदृढ़ करें : सुषमा स्वराज

गत 3 मई को दिल्ली में श्री राजीव प्रताप रूड़ी, सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता की पत्नी श्रीमती नीलम प्रताप रूड़ी के निवास पर कमल सखी मंच की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सदस्यों ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा भाजपा सांसदों की पत्नियों की राय में सम्मति प्रगट की कि सभी को अपने निजी आचरण तथा व्यवहार से संगठन के विचारों को अभिव्यक्त करना आवश्यक है। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती स्वराज ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक 'संखी' का यह उद्देश्य रहना चाहिए कि वे अपने आचरण और कार्यों से लोगों के बीच पार्टी की छवि का निर्माण ही न करें बल्कि उसे मजबूती भी प्रदान करें। सभी को यह मालूम होना चाहिए कि आप अपनी सार्वजनिक उपस्थिति और आचरण के कारण ही भाजपा से जुड़े हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज ने आगे कहा कि भाजपा की महिलाएं राजनीति और परिवार के बीच गहरा सम्बंध स्थापित कर सकती है और जो भी खाई हो, उसमें वे सेतु निर्माण का कार्य कर सकती हैं। हमारी महिला सखियों को पूरे देश में राजनीति तथा राजनीतिक गतिविधियों में भागीदार बन कर प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। बैठक में बताया गया कि 4 मई को सखी के सभी सदस्यों के लिए एक 'हैल्थ एंड फिटनेस' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सदस्यगण श्रीमती कमला आडवाणी के निवास स्थल पर भी गई और वहां श्री लालकृष्ण आडवाणी के जीवन पर एक फिल्म का अवलोकन किया। सखी मंच की संयोजक डा. प्राची प्रकाश जावडेकर ने बैठक में उपस्थित सभी सखियों के प्रति आभार व्यक्त किया। ■